



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

अंतिम जाँच परिणाम

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई तथा ब्राजील से फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी (निर्णायक समीक्षा) जाँच।

सं. 15/19/2008-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. पृष्ठभूमि तथा प्रक्रिया

1. यतः अधिनियम तथा नियम को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण., कोरिया गण., चीनी ताइपेई और ब्राजील (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के प्रारंभिक जाँच परिणाम और अंतिम जाँच परिणाम क्रमशः दिनांक 11-12-2003 तथा 11-11-2004 की अधिसूचनाओं द्वारा प्रकाशित किए गए थे। जाँच परिणामों के आधार पर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर अंतिम शुल्क एवं निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा क्रमशः 20 जनवरी, 2004 और 24 जनवरी, 2005 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने डब्ल्यू सी सं. 2006 की 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत और इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने

की संभावना है, नियमावली के नियम 23 तथा अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा 23 जुलाई, 2008 को शुरू की थी। प्राधिकारी को मै. मनाली पेट्रोकेमिकल लि., चेन्नई से एक उत्तर प्राप्त हुआ था जिसमें संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे इस आधार पर आगे और 5 वर्ष के लिए जारी रखने का अनुरोध किया गया था कि सतत पाटन के कारण घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान सामान्य वांछित लाभ भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है जिसकी वजह संबद्ध देशों से कीमतों का कम स्तर रहा है। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना घरेलू उद्योग के हित में होगा और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से निश्चित तौर पर पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होगी और वह जारी रहेगी।

3. इन कार्रवाइयों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- I. समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को अधिसूचित किया और अधिसूचना जारी होने के 40 दिन के भीतर सूचना मांगी। घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने के बाद अन्य हितबद्ध पार्टियों को उन्हें जारी किए गए पत्रों के 40 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्रों में सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- II. नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित प्रपत्र (प्रश्नावली) में पत्रों के जारी होने के 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- III. किसी भी संबद्ध देश के किसी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया तथा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अतः संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों को असहयोगी निर्यातक माना गया है।
- IV. नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी जांच की शुरुआत के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- V. नियम 6(4) के अनुसार पत्रों के जारी होने के 40 दिन के भीतर आवश्यक सूचना मांगते हुए ज्ञात आयातकों तथा भारत में संबद्ध वस्तु के उपयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियों के साथ जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी भेजी गई थी।
- VI. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में एक आयातक मै. डी पी फोम प्रा.लि. ने उत्तर दिया है। तथापि अन्य आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने अनुमत समय में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उन्हें असहयोगी आयातक/प्रयोक्ता माना गया है।
- VII. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

- VIII. मनाली पेट्रोकेमिकल लि., चेन्नई, जो घरेलू उद्योग का एकमात्र उत्पादक है, ने सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संगत सीमा तक की ताकि हुई क्षति की जांच की जा सके, भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत, उसे बनाने और बेचने की लागत निकाली जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- IX. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए सौदेवार आयात के आंकड़े मांगे गए थे और उनका उपयोग इस जांच में किया गया है।
- X. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां फिक्की, सीआईआई और एसोचेम को भी व्यापक परिचालन हेतु भेजी गई थी।
- XI. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए दिनांक 23-1-2009 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें ब्राजील की सरकार सहित हितबद्ध पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।
- XII. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में और सार्वजनिक सुनवाई के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक चर्चा की गई है जिस सीमा तक वे नियमानुसार संगत हैं और इस मामले पर प्रभाव डालते हैं।
- XIII. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकटित किया गया है और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- XIV. यह जांच 1 अप्रैल, 07 से 31 मार्च, 2008 तक की जांच अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2004-मार्च, 05, अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007 की अवधि और जांच अवधि शामिल है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान समीक्षा एवं मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 3000 से 4000 तक के आणविक भार का फ्लेक्सीबल स्लेबस्टॉक पोलयोल था। फ्लेक्सीबल स्लेबस्टॉक पोलयोल को वाणिज्यिक एवं बाजारी भाषा में आम तौर पर "एफएसपी" के नाम से जाना जाता है और इसे इस समीक्षा में एफएसपी के रूप में ही उल्लेख किया गया है। चूंकि यह मूल जांच की निर्णायक समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

5. एफएसपी अध्याय शीर्ष 3907.20 के अंतर्गत वर्गीकृत है परंतु इसकी निकासी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 3907.99 तथा 3907.91 के अंतर्गत

भी की जाती है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान समीक्षा के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

#### ग. घरेलू उद्योग

6. आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 100% बनता है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

#### घ. हितबद्ध पार्टियों के विचार

घ.1 क्षति एवं पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना पर घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं:

#### पाटन की पुनरावृत्ति तथा उसका जारी रहना

(क) चीन, कोरिया तथा ताइवान:- यह स्पष्ट है कि ऐसे किसी स्रोत से पाटन समाप्त नहीं हुआ है जिन पर आरंभ में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा और उसकी पुनरावृत्ति होगी।

(ख) ब्राजील:- जहां तक ब्राजील का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से बचने के लिए ब्राजील द्वारा जांच अवधि के दौरान निर्यातों को कार्यानीतिक ढंग से समाप्त कर दिया है। तथापि, प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। ब्राजील से वास्तविक आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि ब्राजील के पाटन मार्जिन का निर्धारण अन्य देशों को किए गए निर्यात के आधार पर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा ब्राजील से अन्य देशों को हुए निर्यातों से संबंधित सूचना और उनका पाटन मार्जिन यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिससे यह पता चलेगा कि ब्राजील से पाटन अभी भी जारी है।

#### क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

- (ग) भारतीय पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत क्षति के निर्धारण के सिद्धांत अनुबंध-II में निर्धारित किए गए हैं। अनुबंध के अनुसार क्षति के निर्धारण में पाटन आयातों की मात्रा की तथ्यपरक जांच और घरेलू कीमतों तथा संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों, दोनों पर उसके प्रभाव की जांच शामिल होगी। यह अनुरोध किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में पाटन एवं क्षति का विश्लेषण पाटनरोधी शुल्क की अवधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव के विश्लेषण द्वारा करना अपेक्षित होता है। यह उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है जिससे स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क कारगर रहा है और घरेलू उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तथापि, यह प्रभाव वांछित सीमा तक नहीं रहा है क्योंकि निर्यातक क्षतिकारी पाटन करते रहे हैं। इस प्रकार यह आसन्नवर्ती और स्पष्ट हो जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की अवधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी। ऐसी ही मामला घरेलू उद्योग के बारे में है जिसमें संबद्ध देशों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग के हित में आगे और 5 वर्ष के लिए जारी रखा जा सकता है।
- (घ) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के कुल आयातों में हिस्से में गिरावट आई है। तथापि यह उल्लेख किया गया है कि जांच अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन ब्राजील को छोड़कर, जिसके संबंध में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई आयात न होने की सूचना दी गई है, काफी अधिक रहा है। तथापि, किसी निर्णायक समीक्षा मामले में प्राधिकारी के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की जांच और इस बात की जांच करनी अपेक्षित होती है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने/उसे बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क पिछले साढ़े चार वर्ष से ब्राजील सहित चारों संबद्ध देशों पर लागू था। पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के स्तर और निर्यातकों के इस आशय के भावी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है कि क्या उन्होंने पाटन के व्यवहार में स्थायी तौर पर परिवर्तन किया है/उससे बचाव किया है। इस प्रकार किसी संबद्ध देश से आयातों के अभाव से पाटन के अभाव का पता नहीं चलता है।
- (ङ) यद्यपि, प्रतिशत के रूप में गिरावट आई है, तथापि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में नाटकीय वृद्धि अर्थात् 549 मी.ट. की वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में लगभग 65% की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों ने अभी भी अपनी आक्रामक पाटन की पद्धतियों के जरिए घरेलू बाजार का पर्याप्त भाग कब्जे में किया हुआ है।

- (च) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों की मांग में प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2004-05 में 5.17% से मामूली रूप से घटकर 4.55% हो गया है। घरेलू उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से हुए आयात वर्ष 2004-05 में 8.30% से बढ़कर जांच अवधि में 14.14% हो गए हैं। यह बात निस्संदेह स्पष्ट हो जाती है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में आगे और वृद्धि होगी।
- (छ) संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू बिक्री कीमत से कम है और इनसे घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों की कीमतों में आगे और कमी आएगी।
- (ज) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उन कीमतों से काफी कम है जिन्हें उसने संबद्ध वस्तु की बिक्री पर प्राप्त किया होता। पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से भी कम है।
- (झ) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री भी काफी अधिक रही है। जांच अवधि के दौरान अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री तथा कीमत कटौती से स्पष्ट तौर पर संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में संबद्ध देशों के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार का पता चलता है। घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिसकी वजह से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निश्चित तौर पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री होगी। इसी के साथ-साथ घरेलू उद्योग घरेलू कीमतें कम करने के लिए बाध्य होगा, जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित होगी और परिणामी क्षति होगी।
- (ञ.) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2004-05 में 57.80% से अत्यधिक घटकर जांच अवधि में 33.44% हो गया। इससे संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में पाटित आयातों की स्पष्ट पैठ दिखाई देती है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी। देश में मांग में भारी वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग बाजार में उच्चतर हिस्सा प्राप्त नहीं कर सका है।
- (ट) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के जारी रहने के कारण क्षमता उपयोग अप्रैल, 04-मार्च, 05 के वर्ष में 91% से घटकर जांच अवधि में 88% हो गया अर्थात् 3% की गिरावट आई। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में क्षमता में गिरावट काफी अधिक रही है।

- (ठ) अप्रैल, 04-मार्च, 05 के आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है। तथापि, ऐसा मुख्यतः संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग न किए जाने के कारण हुआ है।
- (ड) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। यह अनुरोध किया गया है कि पाटित आयात जारी रहने के कारण घरेलू उद्योग को भारी घाटा हो रहा है। पूर्ववर्ती वर्षों में लाभकारी स्थिति से घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान भारी घाटे की स्थिति में आ गया है।
- (ढ) यह अनुरोध किया गया है कि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग अभी भी वांछित बिक्री कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। यह भी अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री के साथ-साथ वृद्धि भी हुई है जिससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों में आगे और वृद्धि होगी तथा लाभप्रदता एवं आय के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति आगे और खराब होगी।
- (ण) ब्राजील को छोड़कर, प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक है और यह 27% से 45% के बीच है जिससे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में घरेलू उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों का स्पष्ट पता चलता है। संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन मार्जिन होने से उनके संभावित भावी व्यवहार का पता चलता है और इससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में उनके बाजार हिस्से में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। यह तथ्य कि जांच अवधि के दौरान ब्राजील से कोई आयात होने की सूचना नहीं मिली है, की किसी निर्णायक समीक्षा में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है क्योंकि ऐसे मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत और इस बात की जांच करनी अपेक्षित होती है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने/उसे जारी न रखने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (त) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, क्षति जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में हुई वृद्धि कुल मांग में हुई वृद्धि से कम रही है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मद्देनजर इस बात की प्रबल संभावना है कि इन कारकों में आगे और विकृति आएगी तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी।

- (थ) पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप में और घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि से संबद्ध देशों के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार के बारे में स्पष्ट और मबजूत संकेत मिलता है।
- (द) यद्यपि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आरंभ में कुछ सुधार दिखाई दिया है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग वांछनीय बिक्री कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है जिससे वह पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उचित लाभ अर्जित नहीं कर सका है। यह अनुरोध किया गया है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि संबद्ध देशों से भारी पाटन जारी रहेगा और उसकी पुनरावृत्ति होगी और इससे लाभप्रदता एवं क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति आगे और खराब होगी।
- (ध) यह बात आसन्नवर्ती और स्पष्ट है कि भारी पाटन और आयातों में वृद्धि जारी रहेगी और उसमें आगे और बढ़ोत्तरी होगी। इसके परिणामस्वरूप शुल्क जारी न रखने/उसमें वृद्धि न किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहेगी और उसमें भारी वृद्धि होगी। इसके अलावा इस बात का कोई संकेत नहीं है कि निर्यातकों ने सतत आधार पर पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन किया है या उससे बचाव किया है। उपर्युक्त के मदेनजर यह वांछनीय है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखा जाए और संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों पर उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए।

## घ.2 ब्राजील सरकार का अनुरोध

8. ब्राजील सरकार ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :-

- (ii) ब्राजील ने यह पाया है कि न तो सार्वजनिक सूचना और न ही आवेदन में ब्राजीलियायी निर्यातकों से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में कोई साक्ष्य या टिप्पणी नहीं दी गई है। इसके विपरीत आवेदन में यह उल्लेख है कि उसमें ब्राजील, ताइवान तथा कोरिया में घरेलू कीमतों के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या भरोसेमंद सूचना नहीं दी गई है। वर्ष 2004 से, शुल्क लागू होने के बाद ब्राजील के निर्यात लगभग बंद हो गए हैं और वर्ष 2006-07 में नगण्य मात्रा में निर्यात किया गया है। इसके अलावा, आवेदन में अपुष्ट रूप से यह पुष्टि की गई है कि ब्राजील द्वारा निर्यात पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से बचाव हेतु "कार्यनीतिक रूप से" बंद किए गए हैं।



- (ii) यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 12.3 में यह उल्लेख है कि इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद-11 के अनुसरण में जांच की शुरुआत और समीक्षा पूरी होने पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अनुच्छेद 12.1.1 में यह उल्लेख है कि किसी जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना में किसी पृथक रिपोर्ट के जरिए ऐसे आधार की पर्याप्त सूचना निहित होगी या उसे अन्यथा उपलब्ध कराया जाएगा जिस आधार पर आवेदन में पाटन का आरोप लगाया गया है। यद्यपि आवेदन में यह उल्लेख है कि "घरेलू उद्योग यथासमय सूचना प्रस्तुत करेगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि ब्राजील से पाटन अभी भी जारी है" तथापि, पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में ब्राजील की सरकार को न तो सार्वजनिक सूचना में और न ही आवेदन में खुलासा किया गया है जिससे भारतीय जांच प्राधिकारियों के सार्वजनिक सूचना के दायित्व का साक्ष्यगत उल्लंघन होता है।
- (iii) इसके अलावा, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 में यह उपबंध है कि पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लागू होने से पांच वर्ष से पूर्व की किसी तारीख को समाप्त हो जाएगा जब तक कि प्राधिकारी उस तारीख से पूर्व स्वयं या उक्त तारीख से उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर शुरू की गई किसी समीक्षा में यह निर्धारित न करें कि शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (iv) इस संबंध में यह देखा जाना चाहिए कि पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण करने का भार जांच प्राधिकारियों पर होना चाहिए न कि निर्यातकों पर या निर्यातक देश की सरकार पर। यह निर्धारण मजबूत साक्ष्य पर आधारित होगा न कि अनुमानों पर। इसके अलावा, अमरीकी-डीआरएएमएस पैनल ने अनुच्छेद 11.3 के संदर्भ में अनुच्छेद 11.2 में "संभावना" शब्द की व्याख्या की है। पैनल ने इस बात को प्रदर्शित करने पर बल दिया है कि किसी पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत को साक्ष्य के आधार पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए न कि अनुमानों के आधार पर।
- (v) यद्यपि पाटनरोधी करार में ऐसे साक्ष्य के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं दिया गया है जिसे समीक्षाओं की शुरुआत हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, उसके अनुच्छेद 5 में यह उपबंध है कि किसी पाटनरोधी जांच की शुरुआत के आवेदन में (क) पाटन (ख) क्षति (ग) पाटित आयातों एवं आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का साक्ष्य शामिल होगा। अनुच्छेद 5.3 में भी यह उल्लेख है कि प्राधिकारी आवेदन में उपलब्ध साक्ष्य की यथातथ्यता और पर्याप्तता की

जांच करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या जांच शुरूआत को न्यायोचित ठहराने का पर्याप्त साक्ष्य है ।

- (vi) इस संदर्भ में ब्राजील सरकार इस तथ्य की ओर सादर ध्यान आकर्षित करना चाहेगी कि भारतीय घरेलू उद्योग का आवेदन उपर्युक्त नियम के अनुसार नहीं है ।

### घ.3 मै. डी.पी. फोम प्रा.लि. (आयातक) के अनुरोध

9. मै. डी.पी. फोम प्रा.लि. (आयातक) द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया है :-

- (i) निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी के लिए यह संभावना है कि वह प्रत्येक संबद्ध देश के लिए एक से अधिक सामान्य मूल्य निकाले तथापि प्राधिकारी को इस प्रकार के आकलन हेतु न्यूनतम मूल्य लेना चाहिए । नियम 6(8) में निर्यातकों के असहयोगी की स्थिति में प्राधिकारी के लिए विवेकाधिकार का प्रावधान है । तथापि, इस विवेकाधिकार का उपयोग निष्पक्ष और उचित ढंग से किया जाना चाहिए । इसका प्रयोग एकमात्र बड़े एकाधिकारवादी औद्योगिक/व्यापारित घराने को घरेलू उद्योग के रूप में लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।
- (ii) घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी उद्योग है । पिछले 10 से अधिक वर्षों से उसे वर्ष 1998 में रक्षोपाय शुल्क और यूरोपीय संघ, जापान, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण मिल रहा है । इन देशों का जांच अवधि के दौरान भारत में हुए एफएसपी के कुल आयातों का 93% से अधिक हिस्सा है । घरेलू उद्योग के अनुसार वर्ष 2004-05 और जांच अवधि के दौरान शेष देशों के निर्यात कुल आयातों के मात्र 0.02% से 1.79% तक बनते हैं । सर्वप्रथम रक्षोपाय और तत्पश्चात पिछले 10 से अधिक वर्षों से पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा के बावजूद घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता में सुधार नहीं हुआ है । 12500 मी.ट. की स्थापित क्षमता के साथ घरेलू उद्योग घरेलू मांग के केवल लगभग 50% की पूर्ति करने में समर्थ है । घरेलू उद्योग के अनुसार मांग में 12% वार्षिक से अधिक की दर से वृद्धि हो रही है । तथापि, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में विस्तार हेतु घरेलू उद्योग का कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।
- (iii) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा काफी कम रही है और यह जांच अवधि में हुए कुल आयातों की मात्रा 6.83% बनती है । संबद्ध देशों से आयातों की इतनी कम मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी । घरेलू उद्योग का इस आशय का कोई तर्क कि संबद्ध देशों से आयातों की कम मात्रा पाटनरोधी शुल्क के कारण रही है, को इस कारण से अस्वीकार किया जाना चाहिए कि

वर्ष 2004-05 और जांच अवधि के बीच इन आयातों का औसत पहुंच मूल्य 1472 अम.डॉ./मी.ट. की संदर्भ कीमत से सामान्यतः काफी अधिक रहा है। एकमात्र अपवाद जांच अवधि के दौरान कोरिया से हुए आयातों का पहुंच मूल्य है। स्पष्टतः पाटनरोधी शुल्क पूर्णतः प्रभावहीन रहे हैं और वर्ष 2004-05 के बाद बढ़ती हुई भारतीय मांग को पूरा करने के लिए आयात की मात्रा में भारी वृद्धि नहीं हुई है।

- (iv) यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री मात्रा के बारे में भी अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जबकि वार्षिक रिपोर्ट में विस्तृत सूचना दी गई है।
- (v) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा या उनके बाजार हिस्से में हुई किसी वृद्धि को घरेलू उद्योग की सीमित स्थापित क्षमता और संबद्ध वस्तु की कुल मांग को पूरा करने में उसकी असमर्थता के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा वर्ष 2004-05 में 12.24% से घटकर जांच अवधि में 6.83% हो गया है। संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण नहीं आ सकती है क्योंकि आयातों के उच्च पहुंच मूल्य के कारण पाटनरोधी शुल्क अत्यंत निष्प्रभावी रहा है।
- (vi) संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की बिक्री कर रहा था और वह वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान लाभ कमा रहा था। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुआ आरोपित घाटा संबद्ध देशों से आयातों से इतर कारकों के कारण हुआ है क्योंकि शुल्क पूर्णतः प्रभावहीन रहा है।
- (vii) घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उसे जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ है। यह मानते हुए कि उसे घाटा हुआ है, घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पोलियोल के कारोबार में मात्र 5 करोड़ रूपए की वृद्धि हेतु निम्नलिखित कारण दिए हैं :-

"बिक्री कीमत सीमाशुल्क एवं डॉलर तथा रूपए के मूल्य में समानता का कार्य है जिससे प्रतिस्पर्धी आयातित उत्पादों की पहुंच लागत निर्धारित होती है। मार्च, 2007 में सीमाशुल्क में 5% की कमी की गई थी और वित्त वर्ष की शुरुआत में रूपए में भी 11% तक की भारी मजबूती आई थी और इन कारकों का उत्पाद की बिक्री कीमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था जिससे उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा में वृद्धि होने के बाद भी कुल कारोबार में कमी आई थी।"

वार्षिक रिपोर्ट में यह महज आरोप ही नहीं है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ा था ।

- (viii) जब तक घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता नहीं बढ़ाता है, तब तक वह उच्चतर बाजार हिस्सा प्राप्त करने की अपनी अक्षमता के आधार पर कोई क्षति होने की शिकायत नहीं कर सकता ।
- (ix) वर्ष 2004-05 की तुलना में 3% के कम क्षमता उपयोग के कारण "बाजार परिदृश्य" शीर्षक के अंतर्गत घरेलू उद्योग की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) के पृष्ठ 5 पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं जिसमें यह उल्लेख है कि "तथापि पोलियोल की बिक्री में टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) जो पी यू फॉम के उत्पादन में अपेक्षित पूरक कच्ची सामग्री है, की सतत आपूर्ति संबंधी प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयां आईं ।" स्पष्ट तौर पर क्षमता उपयोग में 3% की कमी टीडीआई के आपूर्ति संबंधी प्रतिबंधों के मद्देनजर घरेलू उद्योग का सुविचारित निर्णय प्रतीत होता है और इसका कारण किसी आरोपित पाटित आयात को नहीं माना जा सकता ।
- (x) बिक्री में गिरावट आरोपित पाटित आयातों के कारण नहीं हो सकती । घरेलू उद्योग ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिबंध टीडीआई की सीमित उपलब्धता के कारण लगाया गया था जो पीयू फॉम के उत्पादन में एफएसपी के साथ एक पूरक सामग्री है, जो बढ़ती हुई चिंता का विषय है और इसे स्वदेशी विनिर्माताओं से टीडीआई का उत्पादन बढ़ाए जाने पर ही सुधारा जा सकता है ।
- (xi) घरेलू रूप से उत्पादित एफएसपी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु से खुली प्रतिस्पर्धा कर रहा था जिसका कारण आयातों की पहुंच कीमत मूल जांच में निर्धारित संदर्भ कीमत का अधिक होना रहा था । वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान घरेलू उद्योग ने वास्तविक लाभ दर्ज किया है । इन लाभों का कारण लागू पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह शुल्क पूर्णतः प्रभावहीन रहा था । अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है ।
- (xii) यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो क्षति की संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों से खुली प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसने वास्तविक लाभ कमाया है ।
- (xiii) वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 में "अवसर एवं खतरे" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 4 में घरेलू उद्योग के उल्लेख के अनुसार भी घरेलू उद्योग के समक्ष इसी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने वाले बड़े विदेशी संयंत्रों से कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है । घरेलू उद्योग के अनुसार खतरा इस कारण से टला है कि खपत में

वृद्धि क्षमता में वृद्धि के अनुरूप रही है। घरेलू उद्योग के अनुसार ऐसे खतरों से कंपनी के प्रचालन पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः संबद्ध देशों में उत्पादन क्षमताओं से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट संभावना नहीं होगी।

#### घ.4 अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर घरेलू उद्योग का अनुरोध

10. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

- (i) अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क किसी अधिकतम अवधि तक लागू रखा जा सके। इसके अलावा, वर्तमान कानून में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें यह निर्धारित है कि शुल्क उस स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता जब घरेलू उद्योग देश की समूची मांग को पूरा करने की स्थिति में हो।
- (ii) आयात की मात्रा ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे जांच समाप्ति का आधार बनाया जा सके क्योंकि निर्णायक समीक्षा पर नियम 14 लागू किया गया है। शून्य आयातों की स्थिति में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने शुल्क की संस्तुति की है क्योंकि उन्होंने पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण किया है। केवल संदर्भ कीमत से अधिक आयात होने का स्वयं अर्थ यह नहीं निकलता है कि आयात अपाटित कीमत पर हुए हैं।
- (iii) जहां तक गोपनीयता के मुद्दे का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने केवल लागत तथा कीमत संबंधी आंकड़ों के बारे में ही गोपनीयता का दावा किया है न कि अन्य सूचना के बारे में।
- (iv) आयातों में कमी की जांच इस बात को ध्यान में रखकर करनी अपेक्षित होती है कि सभी निर्यातकों को इस बात की जानकारी है कि कब निर्णायक समीक्षा की जानी है और उसकी शुरुआत होने की संभावना कब है। इस अवधि के दौरान निर्यातकों का व्यवहार स्पष्ट तौर पर कार्यनीतिक रहा है।
- (v) आयातक ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि में घाटा हुआ है। आयातक ने यह बताया है कि यह घाटा अन्य कारकों से हुआ है। रोचक ढंग से ऐसा अनुरोध करते समय ऐसा कोई अन्य कारक निर्दिष्ट या उल्लिखित नहीं किया गया है।
- (vi) आयातक ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग के लिए शुल्क प्रभावहीन रहा है। इस स्थिति में मध्यावधिक समीक्षा दायर करना जरूरी हो गया था क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में एनआईसी का पुनःनिर्धारण अपेक्षित था। विचाराधीन

निर्णायक समीक्षा के मद्देनजर प्राधिकारी ने मध्यावधिक समीक्षा शुरू नहीं की और घरेलू उद्योग को यह सूचित किया कि ऐसी बदली हुई परिस्थितियों का निर्धारण निर्णायक समीक्षा जांच में किया जाएगा ।

- (vii) अनुरोध करते समय आयातक इस बात को समझने में विफल रहे थे कि निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध की जांच अपेक्षित नहीं होती है । आयातक ने घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से लाभ संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है जो समग्र कंपनी के लिए है न कि विचाराधीन उत्पाद के लिए ।
- (viii) यह उल्लेख किया गया है कि डो केमिकल के अनेक विनिर्माण संयंत्र हैं और कीमत तथा आपूर्ति संबंधी समस्त निर्णय बाजारी गतिशीलता और एकल आर्थिक सत्ता के रूप में विनियामक पहलुओं के आधार पर डो द्वारा लिए जाते हैं । प्राधिकारी स्मरण करेंगे कि डो केमिकल द्वारा आरंभ में अमरीका से निर्यात किया जा रहा था जब शुल्क को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एफएसपी-1 जांच के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था तब उन्होंने तुरंत ब्राजील स्थित अपने संयंत्र से निर्यात शुरू कर दिया और अमरीका से ब्राजील में मांग की पुनः पूर्ति की । ब्राजील से शुल्क की समाप्ति से निश्चित तौर पर ब्राजील से पाटित आपूर्तियों की बहाली होगी (इस बात के मद्देनजर कि डो एकमात्र आर्थिक सत्ता है) और इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पुनः बनेगी जिसमें ब्राजील के विरुद्ध शुल्क लगाकर निजात मिलेगी । ब्राजील से हुए निर्यातों की जांच प्रचालनों की प्रकृति और ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पिछले व्यवहार को ध्यान में रखकर करनी अपेक्षित है ।
- (ix) वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी निदेशकों की अवधारणा में वर्ष 2005-06 में विदेशी संयंत्रों से कोई खतरा मौजूद नहीं था । यह अवधारणा उक्त वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन के जरिए प्रदर्शित की गई है । तथापि, यह नोट करना प्रासंगिक है कि वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित इस प्रकार की अवधारणाएं इस बिना पर आधारित हैं कि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होगी । यदि निर्यातक अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा लेंगे और भारतीय उत्पादक को क्षति पहुंचाने के लिए पाटन करेंगे तो इस प्रकार की अवधारणा का उल्लेख करना भ्रामक और कपटपूर्ण होगा ।
- (x) ब्राजील सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों का हवाला देते समय यह अनुरोध किया गया है कि ब्राजील दूतावास ने जांच शुरूआत के 40 दिन के भीतर उत्तर दायर करने के दायित्व का भ्रमालन नहीं किया है । इसके मद्देनजर अर्जेन्टीना से ऑयल कंट्री टेबूलर गुड्स (डब्ल्यूटी/डीएस 268/एबी/आर 29 नवंबर, 2004) मामले में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार वर्तमान कार्यवाही में उनके पास विधिवत प्रक्रिया का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है ।

- (xi) निर्दिष्ट प्राधिकारी भारतीय पाटनरोधी प्रावधानों (कंपनी कानून) से बंधा हुआ है। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करते समय डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का उल्लेख करना निराधार है। यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 12.3 का हवाला देते समय ब्राजील दूतावास "आवश्यक परिवर्तनों सहित" पद का कोई अर्थ प्रदान करने में विफल रहा है। इस प्रकार अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 12 की शर्तें अनुच्छेद 11.3 पर स्वतः लागू नहीं की जा सकतीं। इस मुद्दे की पुष्टि हाल की दोनों रिपोर्टों अर्थात् ए बी रिपोर्ट (ओसीटीजी मामला डब्ल्यूटी/डीएस 268/एबी/आर तथा कोरोजन रेसिस्टेंट कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स मामला डब्ल्यूटी/डीएस 244/एबी/आर) में पुष्टि की गई है और यह निर्णय निर्णायक समीक्षा मामलों के संदर्भ में दिया गया है। ब्राजील दूतावास द्वारा अमरीकी ड्राम्स मामले का हवाला देना आधारहीन है क्योंकि यह निर्णय मध्यावधि समीक्षा के संदर्भ में दिया गया था न कि निर्णायक समीक्षा मामले के संदर्भ में। दोनों जांचों का उद्देश्य और क्षेत्र अलग-अलग होने के कारण उनके अनुपात को निर्णायक समीक्षा जांच में कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ओसीटीजी मामले में यह निर्णय दिया गया है कि सकारात्मक साक्ष्य को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत किए गए निर्धारण भविष्यलक्षी प्रभाव के हैं और उनमें "भविष्यलक्षी विश्लेषण" शामिल हैं। यह सुनिर्धारित कानून है कि ऐसे किसी विश्लेषण में अनुमानों या भावी संभावनाओं का अनिवार्यतः विश्लेषण होना चाहिए। अपीलीय निकाय द्वारा यह निष्कर्ष निकाल कर उसकी पुष्टि की गई है कि जांच की प्रकृति के मद्देनजर अनुमान की निश्चित सीमा तक संभावना रहेगी और ऐसे किसी परिदृश्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कोई अनुमान "सकारात्मक साक्ष्य" पर आधारित नहीं है। इसके अलावा, कोरोजन रेसिस्टेंट कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स मामले में यह निर्णय लिया गया है कि जांच प्राधिकारियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा में संभावना संबंधी निर्धारण करते समय पाटन मार्जिन की गणना करें या उस पर भरोसा करें। यह भी निर्धारित किया गया है कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें या तो आयात बंद होने के कारण या फिर शुल्क लागू होने के बाद पाटन समाप्त होने के कारण कोई पाटन नहीं हुआ है किन्तु उक्त परिदृश्य केवल शुल्क लगाने के बजाए निर्यातकों के बाजार स्थल या कार्यनीतियों की प्रतिस्पर्धीय स्थितियों में परिवर्तन के कारण मजबूत हुआ है या उसकी आवर्ती हुई है। इसका सुस्पष्ट कारण है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें जांच अवधि के दौरान कोई आयात न हुआ हो और इस प्रकार आवेदन में जांच अवधि के दौरान पाटन का साक्ष्य निहित न हो। वर्तमान मामले में डो केमिकल की कार्यनीति के बारे में हमारे उपर्युक्त अनुरोधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुल्क की अवधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है। स्पष्टतः ब्राजील दूतावास

द्वारा किए गए अनुरोधों में इस विषय पर निर्धारित कानून को ध्यान में नहीं रखा गया है ।

- (xii) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्यातकों ने जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया है ताकि तीसरे देशों के लिए उनकी निर्यात कीमत, उत्पादकों द्वारा क्षमता संवर्धन, मालसूची के बारे में उनकी स्थिति आदि के बारे में सूचना रोकी जा सके । ऐसे व्यवहार के कारण जांच प्रभावित हुई है क्योंकि संभावना के विश्लेषण हेतु अपेक्षित वास्तविक सूचना प्राधिकारी से छिपाई गई है । ऐसी किसी स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाटन जारी है, शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है क्योंकि ये देश धारा 9 (5) के अंतर्गत किए जाने वाले निर्धारण के लिए वास्तविक सूचना उपलब्ध कराने में जानबूझकर विफल रहे हैं ।
- (xiii) घरेलू उद्योग के उपर्युक्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राजील से शुल्क की समाप्ति किए जाने के परिणामस्वरूप ब्राजील से पाटित आपूर्तियों की बहाली होगी और ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाएगी जिसका निवारण ब्राजील के विरुद्ध शुल्क लगाकर होगा ।

#### घ.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग मध्यावधिक समीक्षा कराना चाहता था । तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन एसएसआर के मदेनजर एमटीआर शुरू नहीं की । इस संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि एमटीआर हेतु आवेदन 3 मार्च, 2008 को दायर किया गया था जबकि पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पाटनरोधी शुल्क 19.1.2009 को समाप्त हो रहा था । आगे यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने एसएसआर के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था । दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के मदेनजर प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के 40 दिन के भीतर सूचना दायर करने के लिए घरेलू उद्योग को सलाह देते हुए 23 जुलाई, 2008 को एसएसआर शुरू की थी । तथापि, घरेलू उद्योग ने 25.9.2008 को सूचना प्रस्तुत की । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने शुल्क प्रभावहीन हो जाने की स्थिति में शुल्क में संशोधन की मांग करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई । इसके बजाए उन्होंने निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की प्रक्रिया में विलंब करना उचित समझा ।

12. आयातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा 7% से कम रहा है । अमरीका और सिंगापुर से हुए आयातों का हिस्सा 93% रहा है । यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की इतनी कम मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी । यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में क्षमता के कम उपयोग के कारणों का उल्लेख किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि डीटीआई की सतत आपूर्ति पर प्रतिबंधों के कारण पोलियोल की बिक्री में कठिनाइयां आई हैं जो पीयू फोम के उत्पादन में अपेक्षित एक पूरक कच्ची सामग्री है । हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग



द्वारा क्षमता उपयोग में कमी करना टीडीआई पर आपूर्ति संबंधी प्रतिपूर्ति के मद्देनजर एक सुविचारित निर्णय प्रतीत होता है और इसकी वजह आरोपित पाटित आयात नहीं माना जा सकता। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट में पोलियोल की बिक्री में कंपनी के सामने आई कठिनाइयों और टीडीआई की आपूर्ति संबंधी प्रतिबंधों में इस प्रकार की परेशानी के बारे में उल्लेख किया गया है। अतः प्राधिकारी की मंशा हितबद्ध पार्टियों के इस तर्क से सहमत होने की है कि कम क्षमता उपयोग को कम बिक्री का कारण नहीं माना जा सकता जिसकी वजह बाजारी स्थितियां हैं और आरोपित पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के समक्ष प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा नहीं है।

13. ब्राजील सरकार का यह तर्क कि आवेदक को संभावना के बारे में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए गुणावगुण रहित है क्योंकि निर्यातकों के पास उपलब्ध सूचना को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण करने का भार जांच प्राधिकारी पर होना चाहिए। यह सही है कि प्राधिकारी पर यह दायित्व होता है कि वह पाटन की संभावना का पता लगाने के लिए जांच करे लेकिन यदि सूचनाधारी पार्टी सहयोग करने से मना करती है तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पाटन की कोई संभावना नहीं है। तथापि, प्राधिकारी के लिए उपलब्ध सूचना और समस्त हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगी तर्कों को ध्यान में रखना और उपलब्ध सूचना पर तथ्यपरक नजर रखना अपेक्षित होता है। यह सच है कि घरेलू उद्योग ब्राजील से वास्तविक पाटन के बारे में कोई सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है। तथापि, उसने ब्राजील के निर्यातकों की ओर से पाटन की संभावना के बारे में तर्क अग्रेषित किए हैं। दूसरी ओर, ब्राजील के किसी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और निर्णय लेने के लिए कोई उपयोगी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे यह पता चल सके कि ब्राजील के निर्यातकों ने पूर्ववर्ती वर्षों में पाटन क्यों बंद किया था। अतः प्राधिकारी साक्ष्य के अभाव में घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्राजील के निर्यातकों ने कार्यानीतिक कारणों से भारत को होने वाले पाटित निर्यात बंद कर दिए गए थे।

14. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए अन्य तर्कों पर इस जांच परिणाम में उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है।

**ड** पाटन मार्जिन की गणना के लिए कार्यप्रणाली

**ड1** घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

(क) यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत चीन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। अतः चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

(ख) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रथम विकल्प के रूप में किसी उचित तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन करना अपेक्षित होता है। यह प्रस्ताव किया गया था कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में कोरिया को लिया जा सकता है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग यह मानता है कि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण हेतु कोरिया हेतु क्षमता चीन में विद्यमान विनिर्माण क्षमता के आसपास है। यह भी अनुरोध किया गया है कि कोरिया को इस तथ्य के मद्देनजर प्रतिनिधि देश के रूप में मानने का प्रस्ताव किया गया है कि उद्योग संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी चीन में उपलब्ध इन सुविधों से उचित और निष्पक्ष रूप से मिलती-जुलती हैं, घरेलू उद्योग का कोरिया के किसी उत्पादक से कोई संपर्क या संबंध भी नहीं है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कोरिया बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है जो स्थानीय उत्पादकों और आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसी स्थितियां बाजार निर्धारित कीमतों की बेहतर संकेतक हैं। यह उल्लेख किया गया है कि कोरिया वर्तमान जांच के अधीन एक देश भी है और कोरिया से सामान्य मूल्य के बारे में संगत ब्यौरे जांच की कार्यवाही के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) आवेदक कोरिया, ताइवान और ब्राजील के संबंध में घरेलू कीमतों के बारे में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य या भरोसेमंद सूचना प्राप्त करने में समर्थ रहा है और न ही ये सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

## ड2 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली की प्रति भेजी। चीन जन.गण. के किसी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया और प्रस्तावित प्रतिनिधि देश में सामान्य मूल्य तथा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

## ड3 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. अतः चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

18. सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नानुसार है:

7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा परिकलित मूल्य, अथवा किसी तीसरे

देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा संदेय कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ का समुचित मार्जिन भी शामिल किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा (जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा) और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

19. घरेलू उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में कोरिया गण. पर विचार करने का सुझाव दिया। तथापि, आवेदक कोरिया गण. के उत्पादकों के बारे में आगे कोई सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः प्राधिकारी ने "किसी अन्य उपलब्ध आधार" की पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

#### 34 चीन जन.गण. के लिए परिकलित सामान्य मूल्य

20. सामान्य मूल्य का परिकलन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानक और परिवर्तन लागत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इसमें 5% की ~~ब~~ से लाभ जोड़ा गया है। इस कार्यप्रणाली द्वारा सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. परिकलित किया गया है।

#### 35 चीन जन.गण. के असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

21. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान हुए आयातों के सौदों के आधार पर किया गया है। सीआईएफ निर्यात कीमत का समायोजन विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा, अंतरदेशीय भाड़े एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए किए गए व्यय हेतु किया गया है ताकि कारखाना निर्यात कीमत निकाली जा सके। निर्धारित कारखाना कीमत \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. बनती है।

#### 36 कोरिया गण. के लिए सामान्य मूल्य

22. निर्यातक के असहयोग के मद्देनजर सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर

कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानक और परिवर्तन लागत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इसमें 5% की दर से लाभ जोड़ा गया है। इस कार्यप्रणाली द्वारा सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. परिकलित किया गया है।

#### ड7 कोरिया जन.गण. के असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

23. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान हुए आयातों के सौदों के आधार पर किया गया है। सीआईएफ निर्यात कीमत का समायोजन विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा, अंतरदेशीय भाड़े एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए किए गए व्यय हेतु किया गया है ताकि कारखाना निर्यात कीमत निकाली जा सके। निर्धारित कारखाना कीमत \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. बनती है।

#### ड8 चीनी ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य

24. निर्यातक के असहयोग के मद्देनजर सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानक और परिवर्तन लागत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इसमें 5% की दर से लाभ जोड़ा गया है। इस कार्यप्रणाली द्वारा सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. परिकलित किया गया है।

#### ड9 चीनी ताइपेई के असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

25. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान हुए आयातों के सौदों के आधार पर किया गया है। सीआईएफ निर्यात कीमत का समायोजन विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा, अंतरदेशीय भाड़े एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए किए गए व्यय हेतु किया गया है ताकि कारखाना निर्यात कीमत निकाली जा सके। निर्धारित कारखाना कीमत \*\*\* अम.डॉ./मी.ट. बनती है।

#### ड10. पाटन मार्जिन

26. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया है :-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डा./किग्रा.	निर्यात कीमत अम.डा./किग्रा	पाटन मार्जिन अम.डा./किग्रा	पाटन मार्जिन
------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------

				%
चीन जन.गण.	***	***	***	41.73
कोरिया आरओके	***	***	***	65.31
चीनी लार्डरैड	***	***	***	50.70
बाजिल	किसी पाटन मार्जिन का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान कोई आयात होने की सूचना नहीं दी गई है।			

27. यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

घ. क्षति निर्धारण एवं कारगरत्वक संबंध की जांच हेतु कार्य प्रणाली

घ.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्णायक समीक्षा हेतु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) (5) के संगत उपबंध निम्नानुसार हैं :-

"इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा :

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है तथा आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।"

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में निर्णायक समीक्षा करने की प्रक्रिया दी गई है। समीक्षा करने के लिए नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध लागू किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अनुसार क्षति की वर्तमान स्थिति का आकलन निर्णायक समीक्षा में करना होता है।

30. क्षति की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंधी है, नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों और संकेतकों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन

की मात्रा; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव शामिल होंगे ।

31. क्षति की मौजूदगी और पाटन तथा क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभाव तथा कीमत तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ।

(क) मात्रात्मक प्रभाव: पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव:

32. समस्त स्रोतों से आयातों का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात के सौदेवार आंकड़ों पर भरोसा किया गया है । आंकड़ों से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से हुए आयात आधार वर्ष में 30% से अत्यधिक घटकर जांच अवधि में 2% हो गए हैं । इसी अवधि के दौरान जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, उन देशों से हुए आयात 35% से अत्यधिक बढ़कर 96% हो गए हैं । अन्य देशों से आयात 35.22% से तेजी से घटकर 1.84% हो गए हैं । यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतें वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों की तुलना में अधिक रही थी । जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात कीमतें पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से हुए आयातों की तुलना में मामूली कम रही थी ।

	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
आयात (मी.ट. में)				
चीन जन.गण.	2437	569	311	127
कोरिया जन.गण.	750	1283	645	167
चीनी ताइपेई	79	155	34	103
ब्राजील	0	0	17	0
संबद्ध देश	3266	2007	1007	398
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	3856	7910	12869	16156
अन्य देश	3871	3425	122	206
कुल आयात	10993	13342	13998	16760
आयातों में हिस्सा	%			
संबद्ध देश	29.71	15.04	7.19	2.37
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	35.08	59.29	91.93	96.40
कुल आयात	35.21	25.67	0.88	1.23

मांग, आयात मात्रा तथा बाजार हिस्से का आकलन

33. मांग की गणना घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और समस्त स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में की गई है । यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि

में उत्पाद की मांग में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और इसका हिस्सा आधार वर्ष में 46% से घटकर जांच अवधि में 38% हो गया है। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों का हिस्सा 16% से तेजी से घटकर 1% हो गया है। पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों सहित अन्य देशों से हुए आयातों का हिस्सा 38% से बढ़कर 61% हो गया है।

मांग मी.ट. में	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	9508	10433	10612	10284
आयात-संबद्ध देश	3266	2007	1007	398
आयात - अन्य देश	7727	11335	12992	16362
मांग	20501	23775	24611	27044
बाजार हिस्सा %				
घरेलू उद्योग	46%	44%	43%	38%
आयात-संबद्ध देश	16%	8%	4%	1%
आयात - अन्य देश	38%	48%	53%	61%

#### क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

34. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जांच अवधि)
क्षमता (मी.ट.)	14000	14000	14000	14000
प्रवृत्ति	100	100	100	100
उत्पादन (मी.ट.)	10231	9712	11697	9894
प्रवृत्ति	100	95	114	97
उत्पादन-अन्य-मी.ट.	3827	4013	2364	4357
कुल उत्पादन (मी.ट.)	14058	13725	14061	14251
क्षमता उपयोग %	100.41%	98.04%	100.44%	101.79%

35. जहां तक क्षमता का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक क्षमता का निर्धारण पोलियोल के अन्य ग्रेडों अर्थात् गैर-विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार कम की गई वास्तविक उपलब्ध क्षमता के आधार पर किया गया है। पोलियोल के अन्य ग्रेड के उत्पादन को ध्यान में रखने के बाद यह नोट किया गया है कि वर्ष 2004-05, 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा था। यह तर्क दिया गया है कि क्षमता उपयोग में वास्तविक स्थिति का उल्लेख नहीं होगा, वास्तविक उत्पादन में मांग में वृद्धि के बावजूद स्पष्ट गिरावट प्रदर्शित हुई है। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जब क्षमता का उपयोग विचाराधीन

उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद, दोनों के उत्पादन के लिए किया गया है और विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन पर निर्भर है, तब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन उस स्थिति में घटना जरूरी है यदि उपलब्ध क्षमता का उपयोग गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में किया गया हो। यह स्थिति घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में स्पष्टतः दर्शायी गई है जिसका क्षति अवधि के दौरान पूर्ण उपयोग किया गया है।

36. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से जांच अवधि तक अपनी क्षमता में परिवर्तन नहीं किया है। वस्तु के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है और इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 337 मी.ट. की गिरावट आई है। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन में 1803 मी.ट. की गिरावट आई है। क्षमता के पूर्ण उपयोग की स्थिति में उत्पादन में आई गिरावट पर क्षति के संकेत के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

### बिक्री

37. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है :

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग की बिक्री- मी.ट.	9508	10433	10612	10284
प्रवृत्ति	100	110	112	108
बिक्री मूल्य (लाख रुपए)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	122	122	100

38. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में 8% की बिक्री हुई है। मात्रात्मक रूप में इसमें आधार वर्ष की तुलना में 776 मी.ट. की वृद्धि हुई है। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में 328 मी.ट. की गिरावट आई है।

### (ख) आयातों का कीमत प्रभाव

39. संबद्ध देशों से आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती की गणना करने के लिए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य तथा घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करों, रिबेट, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त छूट और कमीशन का समायोजन किया गया है। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा कीमत कटौती समूची क्षति अवधि के दौरान जारी रही है।



40. यह नोट किया गया है कि कोरिया को छोड़कर वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक संबद्ध देशों से कीमत कटौती नकारात्मक रही थी। जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती लगभग 3% रही थी। संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा भारित औसत आधार पर क्षति अवधि के दौरान कोई कटौती प्रदर्शित नहीं होती है।

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
निवल-बिक्री प्राप्ति रु./मी.	***	***	***	***
पहुंच कीमत- संबद्ध देश				
चीन जन.गण.	88595.19	97912.11	96303.5	80817.81
कीमत कटौती	***	***	***	***
कीमत कटौती %	***	***	***	***
चीनी ताइपेई	104923.4	95449.36	97696.05	76901.52
कीमत कटौती	***	***	***	***
कीमत कटौती %	***	***	***	***
कोरिया आर ओ के	83968.77	93167.02	90567.54	70512.54
कीमत कटौती	***	***	***	***
कीमत कटौती %	***	***	***	***
संबद्ध देश	87925	94689	92654	74462
कीमत कटौती	***	***	***	***
कीमत कटौती %	***	***	***	***

### कम कीमत पर बिक्री

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक प्रमुख संकेतक है। क्षतिरहित कीमत की गणना की गई है और उसकी तुलना संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई है ताकि कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का पता लगाया जा सके। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना के आधार पर परिकलित) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से काफी कम रहा था। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन 25-35% के बीच रहा था।

कम कीमत पर बिक्री (रु./मी.ट.)	
संबद्ध देश	
ब्राजील	*

चीन	***
कोरिया	***
ताइवान	***
कुल	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	
संबद्ध देश	
ब्राजील	*
चीन	***
कोरिया	***
ताइवान	***
कुल	***
कम कीमत पर बिक्री (%)—रेंज	***
संबद्ध देश	
ब्राजील	*
चीन	***
कोरिया	***
ताइवान	***
कुल	***

\* जांच अवधि के दौरान ब्राजील से कोई आयात नहीं हुआ था ।

## च.2 अन्य क्षति मापदंडों की जांच

42. घरेलू उद्योग की मात्रा एवं कीमत पर पाटित आयातों एवं घरेलू उद्योग के आयातों की मात्रा एवं मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री जैसे क्षति के प्रमुख संकेतकों एवं पूर्ववर्ती खंड में विभिन्न खंडों के बाजार हिस्से के साथ मांग की पद्धति की जांच करने के बाद ऐसे आर्थिक मापदंडों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है ।

43. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, लाभ और नकद प्रवाह का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बिक्री मूल्य (लाख रु.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	122	122	100
बिक्री कीमत/इकाई	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	111	109	93
लागत (लाख रुपए)	***	***	***	***
लागत /इकाई	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	111	114	114
लाभ (लाख रुपए)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	127	53	-237

लाभ/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	116	48	-219
लाभ/ हानि (लाख रु.)	***	***	***	***
जोड़िए: मूल्यहास (लाख रु.)	***	***	***	***
नकद प्रवाह (लाख रु.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	119	62	-172
नकद प्रवाह/इकाई	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	108	56	-159

44. घरेलू उद्योग के आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष के 100 की तुलना में जांच अवधि में प्रति इकाई बिक्री लागत बढ़कर 114(सूचीबद्ध) हो गई है। मूल्य के रूप में बिक्री लागत में XXX रु.प्रति मी.ट. की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति आधार वर्ष के 100 की तुलना में जांच अवधि में घटकर 93(सूचीबद्ध) हो गई है। बिक्री कीमत के मूल्य के संबंध में इसमें XXX रु. प्रति मी.ट. की गिरावट आई है। आधार वर्ष में लाभ 100 (सूचीबद्ध) प्रति मी.ट. से घटकर जांच अवधि में XXX के घाटे के स्तर पर आ गया है।

#### नकद प्रवाह

45. घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। अतः घरेलू उद्योग के नकद लाभ की स्थिति का निर्धारण किया गया है। नकद लाभ आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि में क्रम हुआ है और यह सूचीबद्ध रूप में आधार वर्ष में 100 से घटकर जांच अवधि में 159 हो गया है।

#### लगाई गई पूंजी पर आय

46. लगाई गई पूंजी पर आय से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
निवल अचल परिसंपत्तियां रुपए लाख	***	***	***	***
कार्यशील पूंजी रुपए लाख	***	***	***	***
लगाई गई पूंजी	***	***	***	***
ब्याज पूर्व लाभ	***	***	***	***
आरओसीई	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	112	58	-249

47. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में लगाई गई पूंजी में जांच अवधि के दौरान 20% की गिरावट आई है। लगाई गई पूंजी पर आय (एनएफए आधार पर) जो आधार वर्ष में सकारात्मक थी, वह जांच अवधि में नकारात्मक हो गई।

## रोजगार तथा मजदूरी

48. घरेलू उद्योग के रोजगार तथा मजदूरी का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

	अप्रैल 04 से मार्च, 05	अप्रैल 05 से मार्च 06	अप्रैल 06 से मार्च 07	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	90	100	100
कुल मजदूरी (लाख रुपए)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	93	120	113

49. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कर्मचारियों की संख्या समान रही थी। इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों की मजदूरी में 13% की वृद्धि हुई थी।

## उत्पादकता

50. प्रति कर्मचारी उत्पादन के संख्या में प्रदर्शित घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

	अप्रैल 04 से मार्च, 05	अप्रैल 05 से मार्च 06	अप्रैल 06 से मार्च 07	जांच अवधि
उत्पादन (मी.ट.)	***	***	***	***
कर्मचारी	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादन (मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	105	114	97

51. उत्पादन में कमी के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादकता अर्थात् प्रति कर्मचारी उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई।

## वृद्धि

52. मांग, बिक्री एवं बिक्री लागत में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है। उत्पादन, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, पीबीआईटी एवं लगाई गई पूंजी पर अभाव में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है।

## मालसूची

53. आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई । यह आधार वर्ष में 24 दिन की बिक्री के बराबर थी और जांच अवधि में बढ़कर 31 दिन की बिक्री के बराबर हो गई ।

	अप्रैल 04 से मार्च, 05	अप्रैल 05 से मार्च 06	अप्रैल 06 से मार्च 07	जांच अवधि
अथ स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
इति स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
औसत स्टॉक (मी.ट.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	92	104	139
बिक्री मात्रा के % के रूप में	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	84	93	128
धारित स्टॉक की दियस सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	84	93	128

#### घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

54. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध विभिन्न सूचना पर विचार किया । यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन लागत में 14% की वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया गया है कि अयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी । वर्ष 2004-05 में मूल सीमाशुल्क 20% से घटकर जांच अवधि में 10% हो गया, तथापि वर्ष 2006-07 तक पहुंच मूल्य में वृद्धि जारी रही जिसमें जांच अवधि में पर्याप्त गिरावट आई ।

#### पाटन मार्जिन की मात्रा

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन पर्याप्त रहा था ।

#### पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

56. घरेलू उद्योग ने निवेश योजना के बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

#### च.3 वर्तमान क्षति का समग्र निर्धारण

57. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वस्तु की मांग में 32% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। इसी अवधि में उत्पादन में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री में 8% की वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि जांचाधीन उत्पाद एवं गैर-जांचाधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधा समान रही है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के बाद उपलब्ध क्षमता पर निर्भर करता है। चूंकि क्षमता का पूर्ण उपयोग होता रहा, इसलिए उत्पादन में गिरावट को क्षति का संकेत नहीं माना जा सकता। यह भी नोट किया गया है कि बाजार में मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर है। अतः घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट को क्षति का संकेत नहीं माना जा सकता।

58. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में 14% की वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत घटकर 93 (सूचीबद्ध) हो गई है। आधार वर्ष में प्रति इकाई लाभ जांच अवधि में घाटे में तब्दील हो गया। परिणामतः आधार वर्ष की तुलना में लाभ (पीबीआईटी) जांच अवधि में घाटे में आ गया। लगाई गई पूंजी पर आय भी आधार वर्ष में लाभ से घटकर जांच अवधि में नकारात्मक हो गई। वित्तीय निष्पादन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलता है।

#### च.4 अन्य ज्ञात कारक

59. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर निम्नलिखित ज्ञात कारकों की भी जांच की गई है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है अथवा क्षति का कारण हो सकते हैं।

#### अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमत

60. यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क न लगने वाले अन्य देशों (अमरीका, सिंगापुर तथा जापान) से अत्यधिक आयातों की सूचना दी गई है। इन देशों से वे आयात वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में क्रमशः 35.08%, 59.29%, 91.93% और 96.40% रहे हैं। आगे यह नोट किया गया है कि वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में इन देशों से आयात समीक्षाधीन संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में कम रहे थे। वर्ष 2007-08 में संबद्ध देशों से कीमत अन्य देशों की कीमत की तुलना में मामूली कम रही थी।

61. अन्य स्रोतों से आयात (पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से इतर तथा इस समीक्षा के अधीन संबद्ध देशों सहित) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में क्रमशः 35.22%, 25.67%, 0.88% और 1.84% रहे थे। वर्ष 2004-05 को छोड़कर जब कीमतें समीक्षाधीन संबद्ध देशों से कम रही थी, अन्य देशों की तुलना में इन देशों की कीमत अधिक रही थी। तथापि, आयात की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों (समीक्षाधीन देशों को छोड़कर) से हुए आयातों ने आयात बाजार पर कब्जा कर लिया था क्योंकि उनका हिस्सा वर्ष 2006-07 में 91.97% और जांच अवधि में 96.40%

रहा था । ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि जांच अवधि के दौरान इन देशों से आयात कीमत समीक्षाधीन संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में मामूली अधिक रही थी ।

### मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

62. विचाराधीन उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है । तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग टीडीआई, जो पीयू फोम के विनिर्माण हेतु एक पूरक कच्ची सामग्री है, की प्रतिबंधित आपूर्ति के कारण पोलियोल की बिक्री में कठिनाइयों का सामना कर रहा था । इसके अलावा, बाजार में मांग की पूर्ति हेतु घरेलू उद्योग के पास अतिरिक्त क्षमता नहीं है । मांग में कमी ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

### विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

63. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में प्रचलित व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों का कोई साक्ष्य नहीं है । यह कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता । अन्य देशों से संबद्ध वस्तु का बाजार में हुए आयातों में प्राचुर्य रहा है ।

### प्रौद्योगिकी विकास तथा निर्यात निष्पादन

64. उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रौद्योगिकी विकास क्षति का कारण नहीं है ।

### घरेलू उद्योग की उत्पादकता

65. प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में आकलित घरेलू उद्योग की उत्पादकता से यह पता चलता है कि उत्पादकता में उत्पादन में गिरावट के कारण कमी आई है ।

### च.5 कारणात्मक संबंध तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

### च.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क जारी रहने के दौरान घरेलू उद्योग ने क्षमता का उपयोग जारी रखा । उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता गैर-विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन के बाद उपलब्ध रही । विचाराधीन उत्पादन के उत्पादन में गिरावट का कारण क्षमता का गैर-विचाराधीन उत्पादों में उपयोग को माना जा सकता है । तथापि जांच अवधि में यह घटकर 88% हो गया । प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग टीडीआई, जो पीयू फोम के विनिर्माण हेतु एक पूरक कच्ची सामग्री है, की प्रतिबंधित आपूर्ति के कारण पोलियोल की बिक्री में कठिनाइयों का सामना कर रहा

68. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि जब घरेलू उद्योगों के लिए संदर्भ कीमत अप्रासंगिक हो गई है तो उन उद्योगों के लिए उच्च कीमत की आवश्यकता है। संदर्भ कीमत पर वस्तु की बिक्री जारी रखी जा सकती है। प्रमाणित नहीं हुआ था। घरेलू उद्योगों ने यह अनुरोध किया कि देश भर के उद्योगों में कच्ची सामग्री के मूल्य में निजीकरण के कारण 4 फरवरी, 1991 के बाद उद्योगों की संकल्पनाओं से संबद्ध उद्योगों ने एमटीआर घरेलू उद्योगों के लिए उच्च कीमतों का उपयोग अपनी कीमतों की जांच की और बताया कि संदर्भ कीमत एफएसपी-1 की निर्धारित कीमत से उच्च कीमत पर हो सकती है। घरेलू उद्योगों के लिए एमटीआर को दायर करने के लिए एएसएसआर दायर करने के लिए प्राधिकारी द्वारा उच्च कीमत के अभाव का उल्लेख करते हुए



69. यह भी नोट किया गया है कि जांच अवधि में ब्राजील से किसी आयात की सूचना नहीं दी गई है और वर्ष 2006-07 में अत्यंत कम मात्रा में हुए आयात सूचित किए गए हैं। संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क अप्रासंगिक बन गया था क्योंकि ब्राजील से आयात नहीं हो रहे थे जिससे ब्राजील से आयातों की नकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है।

70. क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों से हुए आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई और उसने संबद्ध देशों के बाजार हिस्से को कब्जे में कर लिया। पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की गई है और उसे 6 फरवरी, 2008 से संशोधित किया गया है। संशोधित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का उल्लेख इस समीक्षा की क्षति विश्लेषण में नहीं किया गया है। यद्यपि कोई कीमत कटौती नहीं हुई है तथापि, पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों, संबद्ध देशों की आयात कीमत एवं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कुछ संबंध का पता चलता है क्योंकि आयात कीमत एवं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जांच अवधि में गिरावट आई है। पूर्व में यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और कोरिया गण. से पाटित आयात जारी हैं जैसा कि इस जांच परिणाम के पूर्ववर्ती खंड में आकलन किया गया है। संबद्ध देशों (ब्राजील को छोड़कर) से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क के अधीन अन्य देशों से होने वाले आयात संबद्ध देशों (ब्राजील को छोड़कर) के हिस्से में जाने की संभावना है। अतः संबद्ध देशों (ब्राजील को छोड़कर) से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत क्षति होने की संभावना है।

#### छ. अंतिम जांच परिणाम

71. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

- क. चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और कोरिया गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है जिससे पाटन हुआ है।
- ख. जांच अवधि के दौरान ब्राजील से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया गया है अतः ब्राजील से वर्तमान पाटन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आयातों की प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि ब्राजील से आयात पुनः शुरू नहीं हो सकते हैं।
- ग. चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और कोरिया गण. से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है और इन देशों से हुए पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।

#### भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

72. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

#### ट. सिफारिशें

73. चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और कोरिया गण. से हुए आयातों के पाटन और इस वजह से हुई क्षति की संभावना के सकारात्मक निर्धारण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मत यह है कि इन देशों से हुए आयातों पर बह उपाय जारी रखना अपेक्षित है। तथापि, चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और कोरिया गण. से पाटन के पाटन के वर्तमान स्तर तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि लागू उपाय को संशोधित करने की जरूरत है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और चीनी ताइपेई और कोरिया गण. से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे उल्लिखित प्रपत्र में और ढंग से पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

74. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार चीनी ताइपेई तथा कोरिया गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की जाती है जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

### शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विनिर्देशन	ग्रेड	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3907.20	फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पोलियोल	आणविक भार 3000-4000	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
2	वही	वही		चीन जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
3	वही	वही		पाटनरोधी शुल्क के अधीन देश/देशों से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
4	वही	वही		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
5	वही	वही		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
6	वही	वही		पाटनरोधी शुल्क के अधीन देश/देशों से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
7	वही	वही		चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
8	वही	वही		चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.
9	वही	वही		पाटनरोधी शुल्क के अधीन देश/देशों से इतर कोई देश	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	2601	मी.ट.	अम.डॉ.

75. इस आदेश को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इसके विरुद्ध कोई अपील, अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण में दायर की जा सकेगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2009

**FINAL FINDINGS**

(Sunset Review)

**Subject : Anti-dumping (Sunset Review) investigations concerning imports of Flexible Slabstock Polyol from China PR, Korea RP, Chinese Taipei and Brazil.**

No. 15/19/2008-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, (hereinafter referred to as Act.) as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules.);

**A.BACKGROUND and PROCEDURE**

1. Whereas, having regard to the Act and rules, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Korea RP, Chinese Taipei and Brazil (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings and final findings of the Authority were published vide notifications dated 11.12.2003 and dated 11.11.2004 respectively. On the basis of findings, provisional duty and definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications. dated 20<sup>th</sup> January 2004 and notification dated 24<sup>th</sup> January 2005 respectively.
2. The Authority, in pursuance of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in WC No.16893 of 2006 initiated on 23rd July, 2008, the sunset review of anti-dumping duty imposed on subject goods from subject countries in accordance with section 9A(5) of the Act and Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority received a response from M/s. Manali Petrochemical Ltd, Chennai requesting for review and continuation of the anti-dumping duties levied on the subject goods, for another five years on the grounds that due to continued

dumping, the domestic industry has not been able to realize even the normal desired profits in the period of investigation due to the low level of prices from the subject countries. The continuation of anti-dumping duties would be in the interest of domestic industry and the discontinuance of anti-dumping duties would certainly lead to recurrence and continuance of dumping and injury to the domestic industry.

3. In the proceedings the procedure described below has been followed:
  - I. After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry and called for the information within 40 days of the issue of the notification. On receipt of the information from the domestic industry, other interested parties were provided opportunity to submit information in the prescribed formats within 40 days of the letters issued to them.
  - II. All known exporters/producers in the subject countries were given opportunity to submit information within 40 days of issue of the letters on prescribed proforma (questionnaire) and necessary information in accordance with Rule 6(4);
  - III. No exporter from any subject countries responded and provided any information. Therefore all exporters from subject countries have been treated as non cooperating exporters.
  - IV. The Embassies of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
  - V. A copy of initiation notification along with the importers questionnaire was also sent to the known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information within 40 days of issue of the letters in accordance with Rule 6(4).
  - VI. In response to the above notification, M/s D.P. Foam Pvt. Ltd, an importer has filed the response. However, other importers or users has not filed response to the questionnaire in the permitted time. Therefore, they have been treated as non-cooperating importers/users.
  - VII. The Authority kept available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties in accordance with Rule 6 (7).
  - VIII. Manali Petrochemical Ltd, Chennai, only producer of the domestic industry, submitted the information/data. The Authority examined the information furnished by the domestic industry to the extent considered relevant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to examine the

injury suffered, to work out optimum cost of production, cost to make and sell the subject goods in India and so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;

- IX. Transaction-wise data of imports for the period of investigation and preceding three years were called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and has also been used in this investigation;
- X. Copies of the initiation notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.
- XI. The Authority held a public hearing on 23.1.2009 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of interested parties including Government of Brazil. The written submissions and rejoinders received from interested parties to the extent considered relevant have been considered by the authority;
- XII. The views expressed by various interested parties in response to the initiation notification and subsequent to the public hearing have been discussed in the relevant paragraphs to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case.
- XIII. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for the findings have been disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings.
- XIV. Investigations were carried out for the period of investigation (POI) from 1st April 07 to 31st March 2008. The injury investigation period however covered the periods April,2004-March,05, April,2005-March,2006, April,2006-March,2007 and the POI.

## **B PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

- 4. The product under consideration in the present review and in the original investigation was Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000. The Flexible Slabstock Polyol is generally known as "FSP" in the commercial and market parlance and has also been referred to as FSP in this review. This being sunset review of original investigation, therefore there is no change in scope of product under consideration.
- 5. FSP is classified under Chapter Heading 3907.20 but are also cleared under Chapter Headings 3907.99 and 3907.91 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present review.

**C. Domestic industry**

6. The applicant account for 100% of Indian production and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

**D. Views of the Interested Parties****D.1 Submissions of the Domestic Industry on injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury**

7. The domestic industry has made the following submissions:-

**Recurrence and continuation of Dumping**

- a) China, Korea and Taiwan:- It is clear that the dumping has not ceased to exist from any of these sources on which anti dumping duties were imposed initially. Therefore, there is every likelihood that the dumping would continue and recur in case the duties are discontinued.
- b) Brazil: As far as Brazil is concerned, it appears that the exports by Brazil have strategically ceased during the POI to avoid continuation of anti dumping duties. However, the Authority is required to examine whether the cessation of existing anti dumping duties is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury in the event the anti dumping duties are removed. In the absence of actual imports from Brazil, the domestic industry submits that the dumping margin for Brazil may be determined based on the export made to other countries. The domestic industry would submit the information relating to exports to other countries by Brazil and their dumping margin in due course which would indicate that the dumping is still continuing from Brazil.

**Likelihood of continuance or recurrence of injury**

- c) The principles for the determination of injury under the Indian Anti-dumping Rules have been prescribed under Annexure II. As per the Annexure, the determination of injury shall involve an objective examination of the volume of dumped imports and its effect both on the domestic prices and as well as the domestic producers of the subject goods. It has been submitted that in case of sunset review investigation, dumping as well as injury analysis is required to be made by analyzing the likely impact on the domestic industry in the event the anti-dumping duties are not extended. It has been pointed out that the situation of the domestic industry has improved after the imposition of the anti-dumping duties, clearly indicating that the anti-dumping duties have been effective and there has been a positive impact on the domestic industry. However, the effect has not been to the desired extent as the exporters have continued to indulge in injurious dumping. Thus, it is imminent and clear that the dumping and injury to the domestic industry would continue if the anti-dumping duties are not extended. It is the case of the domestic industry that the anti-dumping duties against the subject countries may be

continued for another term of 5 years in the interest of the domestic industry

- d) The share of subject countries in total imports has declined during the period of investigation. However, it has been pointed out that the dumping margin from each of the subject countries during the period of investigation is also significant except in case of Brazil for which no imports of the subject goods have been reported during the period of investigation. However, in a sunset review case, the Authority is required to examine the need for continued imposition of anti-dumping duties in force and whether the cessation/ discontinuance of anti-dumping duties in force is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury. It has been pointed out that the anti-dumping duties were in existence against the four subject countries including Brazil during the last four and a half years. The analysis of dumping and injury to the domestic industry is required to be made keeping in view the level of anti-dumping duty in existence and the likely future behaviour of the exporters as to whether they have permanently changed / abstained from the behaviour of dumping. Thus, absence of imports from a subject country does not indicate absence of dumping.
- e) Though there has been a decline in terms of percentage, there has been a phenomenal increase in absolute terms i.e., an increase of 549 MT during the POI as compared to the base year. In terms of percentage there has been an increase of about 65%. This definitely goes to prove that the subject countries still hold a substantial slice of the domestic market through their aggressive dumping methods
- f) The percentage share in demand of imports from subject countries has declined marginally from 5.17% in 2004-2005 to 4.55% during the period of investigation. Imports from subject countries in comparison to domestic production have increased from 8.30% in the 2004-2005 to 14.14% during the period of investigation. It is undoubtedly clear that the imports from subject countries will increase further in case the duty is withdrawn.
- g) The landed value from the subject countries is less than the domestic selling prices and the same are undercutting the domestic prices. It clearly indicates that the prices from the subject countries will further be reduced in case the anti-dumping duties are discontinued.
- h) The landed value of the product under consideration from the subject countries is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods and the net sales realization of the domestic industry.
- i) The price underselling from the subject countries is significant during the period of investigation. The level of significant price underselling and undercutting during the period of investigation clearly indicates the likely future behaviour of the exporters from the subject countries regarding the pricing of the subject goods. The domestic industry has demonstrated that

the exports from the subject countries are being made at such prices that removal of anti-dumping duties would certainly lead to price undercutting and price underselling. Correspondingly, the domestic industry would be forced to reduce the domestic prices, which would affect their profitability and the resultant injury.

- j) The share of the domestic industry has declined during the period of investigation as compared to the base year. The percentage share has come down sizably from 57.80% in 2004-2005 to 33.44% during the period of investigation. This is a clear reflection of the penetration of dumped imports in the Indian market from the subject countries. It is clearly evident that the injury to the domestic industry would recur in case the duties are discontinued. Despite a huge increase of demand in the country, the domestic industry has not been able to achieve higher share in the market.
- k) Due to the continuance of the dumped imports from the subject countries during the period of investigation, the capacity utilization has declined from 91% in the year April 04-March 05 to 88% during the period of investigation, a decline of 3%. The decline in capacity during the period of investigation is much more as compared to the immediately previous year.
- l) There is a minimal decline in the productivity per employee during the period of investigation as compared to the base year April 04-March 05. However, this is mainly because the domestic industry has not been able to utilize its optimum capacity due to presence of dumped imports from the subject countries.
- m) The domestic industry's profitability position showed some improvement due to the imposition of anti-dumping duties. It has been submitted that the domestic industry is suffering huge losses due to the continuation of dumped imports. From a profit-making scenario in the preceding years, the domestic industry is incurring huge amount of losses during the period of investigation.
- n) It has been submitted that the domestic industry is still not able to realize the desirable selling price due to the presence of dumped imports. It has also been submitted that dumped imports from the subject countries have also increased coupled with significant price underselling, clearly indicating that the imports from subject countries would increase further and deteriorate the situation of the domestic industry in terms of its profitability and return.
- o) The dumping margin from each of the subject countries except Brazil is significant and ranges between 27% to 45% clearly indicate the difficulties being faced by the domestic industry to sell the subject goods in the domestic market. The significant dumping margin from the subject countries clearly indicates their likely future behaviour and the same would further increase in all probability to increase their market share in India in case of discontinuation of anti-dumping duties. The fact that Brazil has reported no imports during the POI has no relevance in a sunset review as in such cases, the HDesignated Authority is required to examine the need



for continued imposition of anti-dumping duties in force and whether the cessation / discontinuance of anti-dumping duties in force is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury.

- p) The sales volume of the domestic industry has increased during the period of investigation. However, the growth in sales volume of the domestic industry over the injury investigation period is less than the growth in the total demand. Moreover, the market share of the domestic industry has come down during the period of investigation as compared to the base year. This clearly shows that the domestic industry is injured with respect to growth. There is every likelihood in view of the dumped imports from the subject countries that these factors would further deteriorate and the injury to the domestic industry would continue or recur.
- q) The imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to the domestic production, despite the existence of anti dumping duties. The increase in imports from the subject countries during the injury investigation period gives a clear and strong indication about the likely future behaviour of the exporters from subject countries.
- r) Although the profitability of the domestic industry has shown some improvement initially, there has been a huge dip in the profitability during the POI as compared to the preceding years. Moreover, the domestic industry has not been able to realize the desirable selling price which has not allowed it to earn reasonable returns due to the presence of dumped imports. It has been submitted that there is every possibility that the severe dumping from the subject countries would continue and recur and further deteriorate the position of the domestic industry in terms of its profitability and injury.
- s) It is imminent and clear that severe dumping and increase in imports would continue and further increase. It would then consequently lead to continuation and imminent increase of injury in case the duties are not continued /enhanced. Moreover, there is no indication that the exporters have changed or abstained from their behaviour of exporting the subject goods at dumped prices on a sustainable basis. In light of the above, it is desirable that the anti-dumping duties should continue to be imposed and their level enhanced against the dumped imports from the subject countries.

## **D.2 Submissions by Brazilian Government**

8. The Brazilian Government has made the following submissions:-

- (i) Brazil notices that neither the public notification nor application, bring on their content any evidence or comment regarding the likelihood of continuation or recurrence dumping from Brazilian exporters. On the contrary, the application states that it does not bring any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in Brazil, Taiwan and Korea. Since 2004, after the application of the duties, Brazilian exports have almost ceased, with a negligible volume being

exported in 2006-07. Nonetheless, the application unsustainably affirms that the export by Brazil have 'strategically' ceased to avoid the continuation of anti dumping duties.

- (ii) It has been submitted that Article 12.3 of the Antidumping Agreement states that the provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the initiation and completion of reviews pursuant to Article 11. Article 12.1.1, on its turn, states that a public notice of the initiation of an investigation shall contain, or otherwise make available through a separate report, adequate information on the basis on which dumping is alleged in the application. Although the application states that "the domestic industry would submit the information in due course which would indicate that dumping is still continuing from Brazil", no data on the likelihood of continuation or recurrence of dumping was disclosed to the Brazilian Government neither in the public notification, nor in the application, in evidence breach of the public notice obligations of the Indian investigating authorities.
- (iii) Furthermore, Article 11.3 of the Antidumping Agreement provides that notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti dumping duty shall be terminate on a date not later than five years from its imposition, unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- (iv) In this regard, it should be noticed that the burden to determine the likelihood of continuation or recurrence of dumping must be borne by the investigating authorities, not by the exporters or the government of the exporting country. This determination shall be based on strong evidence, not on presumptions. Furthermore, the US-DRAMS Panel interpreted the term "likely" in Article 11.2 with reference to Article 11.3. The Panel reinforced the necessity to demonstrate the need for the continued imposition of an anti-dumping duty should be demonstrable on the basis of evidence, and not on presumptions.
- (v) Although the antidumping Agreement does not bring specific rules regarding the evidence that should be presented for the initiation of reviews, in its Article 5 it provides that an application to the initiation of an antidumping investigation shall include evidence of (a) dumping (b) injury (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Article 5.3 also states that authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation.

- (vi) In this context, with due respect, the Government of Brazil would like to bring attention upon the fact that Indian domestic industry's application does not comply with the rule mentioned above.

### D.3 Submissions by M/s D.P. Foam Pvt. Ltd.(Importer)

9. M/s D.P. Foam Pvt. Ltd. have made the following submissions:-

- (i) In view of the non-cooperation by the exporters, it is possible for the Authority to arrive at more than one normal value for each of the subject countries, the Authority should take the lower of the values so arrived at. The Rule 6(8) provides discretion to the Authority in case of non-cooperation by the exporters. However, this discretion ought to be exercised in a fair and reasonable manner. It ought not to be exercised to benefit a single large monopolistic industrial/business house as the domestic industry.
- (ii) The domestic industry is a monopolistic industry. For the last more than 10 years, it is having protection of safeguard duties in the year 1998 and anti dumping duties in respect of European Union, Japan, Singapore and United State of America. These countries account for more than 93% of total imports of FSP into India during the POI. As per the domestic industry, the remaining countries exports constitute a mere 0.02% to 1.79% of the total imports between 2004-05 and the Period of Investigation. Despite the protection of first the safeguard duties and thereafter, the anti dumping duties for the last more than ten years, the domestic industry's competitiveness and efficiency has not improved. The domestic industry with installed capacity of 12500 MT is able to satisfy around 50% of the total demand only. As per the domestic industry, the demand is growing at the rate of more than 12% per annum. However, there is not a single proposal of the domestic industry to expand its capacity to meet the growing demand.
- (iii) Volume of imports from subject countries has been very low and constitute a mere 6.83% of the total imports in the POI. Such small volume of imports from subject countries would not cause injury to the domestic industry. Any argument by the domestic industry that a low volume of imports from subject countries was attributable to anti dumping duties is liable to be rejected for the reason that average landed value of these imports during the period between 2004-05 and the POI were generally much higher than the reference price of US\$1472/MT. The only exception being the landed value of imports from Korea during the POI. Clearly, the anti dumping duties were completely ineffective, and yet, the volume of imports did not substantially rise after 2004-05 to meet the growing Indian demand.
- (iv) It has been submitted that the domestic industry has claimed excessive confidentiality even on capacity, production and sales volume whereas the Annual Report gives the detailed information.

- (v) Any increase in the volume or market share of imports from the subject countries must be viewed in light of limited installed capacity of the domestic industry and their inability to meet the total demand of the subject goods. The share of imports from the subject countries as a percentage of the total imports has come down from 12.24% in 2004-05 to 6.83% during the POI. This decline in market share of imports from the subject countries cannot be attributed to anti dumping duties in force since the anti dumping duties were not at all effective in view of the high landed value of the imports.
- (vi) The imports from subject countries are not having any effect on the domestic price. The domestic industry was able to sell their products and was enjoying profits during 2004-05 to 2006-07. The alleged losses suffered by the domestic industry during the POI are on account of factors other than the imports from subject countries as duties were completely ineffective.
- (vii) The domestic industry has alleged that it has suffered losses during the POI. Assuming that it did suffer losses, the domestic industry has given reasons in its Annual Report for the increase in turnover of polyol by a mere Rs.5 crores as follows:-
- “Selling price is a function of the customs duty and the dollar to rupee parity, which determine the landed cost of competing imported products. The customs duty was reduced during March 2007 by 5% and the rupee also appreciated sharply by 11% around the beginning of the financial year and thus these factors had a significant effect on the selling prices of the product, which reduced the turnover, even though the quantum of production and sales have gone up.”
- There is not even an allegation in the Annual Report that the imports of the subject goods from the subject countries had any effect on the domestic prices.
- (viii) Unless the domestic industry increases its capacity to meet the growing demand, it cannot complain of suffering any injury on the ground of its inability of achieving higher market share.
- (ix) The reasons for a lower capacity utilization by 3% over 2004-05 is clear on page 5 of the 22<sup>nd</sup> Annual Report of the Domestic Industry (2007-08) under the heading “Market Scenario” as “the polyol sales however encountered difficulties due to continued supply restrictions of Toluene Di-Isocyanate (TDI), the complimenting raw material required in the production of PU foam”. Clearly, the reduction in capacity utilization by 3% appears to be a conscious decision of the Domestic industry in view of the supply restrictions of TDI, and cannot be attributable to any alleged dumped imports.
- (x) The decrease in sales cannot be attributed to the alleged dumped imports. The domestic industry also admits that the restrictions posed

by the limited availability of TDI, the complementary raw material along with FSP in the production of PU Foam, is a growing concern and can be improved only with increased production of TDI from the indigenous manufacturers.

- (xi) The domestically produced FSP was openly competing with the subject goods from the subject countries because of the landed price of the imports being higher than the reference price fixed in the original investigation. The domestic industry has booked actual profits during 2004-05, 2005-06 and 2006-07. These profits cannot be attributed to the protection of the anti dumping duties in force since the duties were completely ineffective. Therefore, injury is not likely to continue or recur if the duties are removed.
- (xii) Injury is not likely to recur if the anti dumping duties are removed because domestic industry has been openly competing with the imports from subject countries during the injury period and has enjoyed actual profits.
- (xiii) Even as per the statement of the domestic industry in paragraph 4 of its Annual Report 2005-06 under the "Opportunities and Threats", the domestic industry does not see any threat from large foreign plants producing similar products. The absence of threat, according to the Domestic Industry, is for the reason that the increase in consumption matches the increase in capacity. According to the domestic industry, such threats will not affect the operations of the company significantly. Clearly, therefore, the production capacities in the subject countries would not cause any continuation or recurrence of injury if the anti dumping duties were removed.

#### **D.4 Submissions by the domestic industry on the issues raised by other interested parties**

10. The domestic industry have made the following submissions:-

- (i) There is no provision under the Act or Rules which limits the applicability of the anti dumping duty for a maximum period. Further, there is no provision under the present law which lays down that duties can be imposed only when the domestic industry is in a position to meet entire demand of the country.
- (ii) The quantum of import is not a fact that can be a basis of termination as Rule 14 has been made inapplicable to the Sunset Review. Even in a situation of nil imports, the Designated Authority has recommended duties as it determined likelihood of dumping and injury. Merely because, the imports have taken place above reference price, does not *ipso facto* mean that imports are non-dumped.

- (iii) Concerning issue of confidentiality, it has been submitted that domestic industry has claimed confidentiality only on cost and price data and not on the other information.
- (iv) The reduction of imports are required to be examined keeping in view that all exporters know exactly when the Sunset Review is due and is likely to be initiated. Clearly the behavior of the exporters during this period is strategic.
- (v) The importer has not disputed that there was loss suffered by the domestic industry during POI. It has been stated by the importer that this loss is on account of other factors. Interestingly, no such other factors have been specified or referred to while making such submissions.
- (vi) The importer has admitted that duties were ineffective for the domestic industry. This situation had necessitated filing of a mid-term review as the NIP was required to be re-determined in view of the changed circumstances. The Authority in view of the impending Sunset Review had not initiated the mid-term review and had indicated to the domestic industry that such changed circumstances would be addressed in Sunset Review investigations.
- (vii) While making submissions, the importers had failed to appreciate that causal link is not required to be examined in Sunset Review. The importer has relied upon profit figures from the Annual Report of the domestic industry which is for the company as a whole and not for the product under consideration.
- (viii) It has been pointed out that Dow Chemical has number of manufacturing plants and all pricing and supply decisions are taken by the Dow based on market dynamics and review of regulatory aspects as a single economic entity. The Authority would recall that Dow Chemical's was initially exporting from USA. When duties were notified by the Designated Authority under FSP-1 investigation, they immediately started exporting from their plant in Brazil and replenish demand in Brazil from USA. Removal of duties from Brazil would certainly result in resumption of dumped supplies from Brazil (keeping in view that Dow is a single economic entity) and would result in recurrence of a situation that was sought to be addressed by imposition of duties against Brazil. The exports from Brazil have required to be examined keeping in view the nature of operations and past behavior of such multinational companies.
- (ix) Referring to the Annual Report, it has been submitted that in the perception of the directors of the company there existed no threat from foreign plants in the year 2005-06. This perception is in fact reflected through the performance of the company during that year. However, it is pertinent to note that such perceptions mentioned in the Annual Reports are based on a premise that there would be fair competition. If

exporters resort to unfair competition and resort to dumping to destroy the Indian producer, the reference to such perception is hence misleading and mischievously made.

- (x) While referring to the submissions made by Brazilian Government, it has been submitted that the Embassy of Brazil has not respected its obligation to file a response within 40 days of initiation. In view thereof, in terms of WTO decision of Appellate Body in the case of Oil Country Tubular Goods from Argentina (WT/DS268/AB/R 29 November 2004) they have no due process rights available to them in the present proceedings.
- (xi) The Designated Authority is bound with the Indian anti-dumping provisions (municipal law). Reference to WTO Agreement on Anti-dumping is hence misplaced while making submissions before the Designated authority. It has been pointed out that while referring to Article 12.3, Embassy of Brazil failed to give any meaning to the term "motu proprio". Hence the conditions of Article 5 or Article 12 cannot ipso facto be applied to Article 11.3. This issue has been finally confirmed by both the recent AB reports (OCTG Case WT/DS268/AB/R and Corrosion Resistant Carbon Steel Flat Products case WT/DS244/AB/R) and rendered in the context of sunset review cases. The reference by Embassy of Brazil to US Drums case is misplaced as the decision was rendered in the context of mid-term review and not sunset review case. The object and scope of investigations being different the ratio of the same cannot be borrowed in sunset review investigations. Further in the OCTG case it has been held that positive evidence must be seen in the context that the determinations to be made under Article 11.3 are prospective in nature and that they involve a "forward-looking analysis". It has been settled law that such an analysis may inevitably entail assumptions about or projections into the future. It has been concluded and confirmed by the Appellate Body that in view of the nature of enquiry, unavoidably there would be certain extent of speculation and in such a scenario it cannot be said that such inferences are not based on "positive evidence". Further in Corrosion Resistant Carbon Steel Flat Products case it has been held that investigating authorities are not required to calculate or rely on dumping margins in making a likelihood determination in sunset review under Article 11.3. It has also been laid down that there may arise a situation when there is no dumping either because imports ceased or because dumping was eliminated after the duty was imposed but that scenario could have been caused or reinforced by changes in the competitive conditions of the market place or strategies of the exporters, rather than by the imposition of duty alone. This is precisely the reason that there may be a situation when there is no import during POI and hence the application may not contain evidence of dumping in POI. In the present case our above submissions on strategy of Dow Chemical's makes it clear that imports are likely to surge if the duties are not extended. Clearly, the submissions made by



the Embassy of Brazil are without taking into account settled law on the subject.

- (xii) It is evident from the facts and circumstances of the present case that the exporters have consciously not cooperated in the investigation with a view to withhold information about their export price to third countries, addition of capacities by producers, their inventory position etc. Such behavior has resulted in impeding the investigation as material information required for likelihood analysis has been withheld from the authority. In such a scenario, and the fact that dumping continues, the duties are required to be continued as these countries consciously failed to provide material information to reach determinations required to be made under Section 9A(5).
- (xiii) In view of aforementioned submissions of domestic industry, it is amply clear that removal of duties from Brazil would for certain result in resumption of dumped supplies from Brazil and would result in recurrence of a situation that was sought to be addressed by imposition of duties against Brazil.

#### **D.5 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

11. It has been stated that domestic industry wanted to add mid-term review, however, the Designated Authority did not initiate MTR in view of impending SSR. In this regard, it has been noted that the application for MTR was filed on 3<sup>rd</sup> March 2008, the anti dumping duty was going to expire on 19.1.2009 on completion of five years term. The applicant was therefore advised to file SSR. It has further been noted that the applicant did not file any application for SSR. The Authority in view of the Judgment of Delhi High Court initiated SSR on 23<sup>rd</sup> July 2008 advising domestic industry to file information within 40 days of initiation. The domestic industry however chose to file the information on 25.9.2008. The Authority notes that the domestic industry did not show any urgency in seeking revision of duty if the duty had become ineffective instead it choose to delay the process of initiation of sunset review.

12. It has been contended by the importer that share of imports from subject countries have come down less than 7%. Imports from USA and Singapore account for 93% of imports. It has been contended that such small volume of imports from subject countries would not cause injury to the domestic industry. It has also been pointed out that reasons for lower capacity utilization has been stated in the Annual Report of the applicant where it has been stated that the Polyol sales however encountered difficulties due to continued supply restrictions of TDI, the complementing raw material required in production of PU foam. It has been contended by the interested parties that the reduction in capacity utilization by the domestic industry appears to be a conscious decision in view of the supply restriction of the TDI and cannot be attributable to any alleged dumped imports. The Authority, in this regard notes that 22<sup>nd</sup> Annual Report of the applicant point out about the difficulties faced by the company in Polyol sales and reason assigned to such difficulty is supply restriction of TDI. The Authority therefore intends to agree with



the contention of the interested parties that lower capacity utilization can be attributed to lower sales because of market conditions and not necessarily because of the competition faced by domestic industry from the alleged dumped imports.

13. The contention of Brazilian Government that applicant should provide all evidence on likelihood, is devoid of merit as information which is available with the exporters cannot be expected to be provided by the domestic industry. It has also been argued that the burden to determine the likelihood of continuance or reoccurrence of dumping must be borne by the investigating authority. It is correct that the Authority is under obligation to conduct investigation to ascertain likelihood of dumping, however, if the party holding information refuses to cooperate, it cannot be concluded that there is no likelihood of dumping. The Authority is however required to take into account available information and persuasive arguments forwarded by all interested parties and take objective view of the available information. It is a fact that domestic industry has not been able to provide any information about actual dumping from Brazil, however, it has forwarded argument about the likelihood of dumping from the Brazilian exporters. On the other hand, no exporters from Brazil has cooperated and provided any useful information for arriving at decisions. The Authority however notes that as no information has been made available as to why Brazilian exporters discontinued dumping in the preceding years. therefore, the Authority in absence of evidence cannot accept the argument of the domestic industry and conclude that Brazilian exporters discontinued dumped exports to India for strategic reasons

14. The other arguments raised by various interested parties have been dealt in the findings at appropriate places.

## **E METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN**

### **E.1 Submissions by the domestic industry**

15. The Domestic Industry has made the following submissions-

- a) It has been submitted that China is a non-market economy country under the Indian Anti-dumping Rules. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules.
- b) For the purpose of determination of normal value in case of a non-market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. It was proposed that Korea be taken as an appropriate market economy third country. It has been submitted that the domestic industry understands that the capacity in Korea for manufacturing the subject goods is close to the manufacturing facility in China. It has also been submitted that Korea is proposed as a surrogate country in view of the fact that the industry structure, the average capacity of plants, the cost structure, the production process and the technology are reasonably and fairly close to that found in China. The domestic industry also has no links or relationship with any of the producers in Korea. This proposition is also guided by the fact that Korea is a market economy country with considerable competition within the local producers as well as

from imported goods. Such conditions are a good indicator of market determined prices. It has been stated that the Korea is also a country under the present investigation and the relevant details for normal value from Korea can be obtained during the course of investigation.

- c) The applicant has neither been able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in respect of Korea, Taiwan & Brazil nor are the same available in the public domain.

## **E.2 Examination by the Authority**

16. The Authority sent a copy of exporter's questionnaire and market economy questionnaire to known exporters in China PR. No exporter from china PR has responded and provided any information concerning market economy treatment and about the normal value in the proposed surrogate country.

## **E.3 Normal Value for China PR**

17. Therefore, the normal value for the China-PR has been determined in accordance to para 7 of Annexure-1 of the Rules.

18. Para 7 of the Annexure-1 with regard to determination of normal value provides as follows—

*7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

19. The domestic industry suggested consideration of Korea RP as appropriate market economy third country. The applicant however has failed to submit any further information about producers in Korea RP. The authority, therefore, has determined normal value on the basis of method 'on any other reasonable basis'.

#### **E.4 Constructed Normal value for China PR**

20. The normal value has been constructed on the basis of raw material at international prices to India, consumption norm and conversion cost of the domestic industry. To this, profit @ 5% has been added to determine normal value. By this methodology the normal value has been constructed as US\$ \*\*\*/MT.

#### **E.5 Export price for non-cooperating exporters from China PR**

21. Export price for non cooperative exporters has been determined on the basis\* of transactions of imports during the POI based on the information made available by DGCI&S. The CIF export price has been adjusted for expenses on account of overseas freight, overseas insurance, inland freight and handling charges to arrive at ex factory export price. The ex-factory price determined comes to US\$ \*\*\*/MT.

#### **E.6 Normal value for Korea RP**

22. In view of non-cooperation by exporter, the normal value has been constructed on the basis of facts available as per Rule 6(8). The normal value has been constructed on the basis of raw material at international prices, consumption norm and conversion cost of the domestic industry. To this, profit @ 5% has been added to determine normal value. By this methodology the normal value has been constructed as US\$ \*\*\*/MT.

#### **E.7 Export price for non-cooperating exporters from Korea RP**

23. Export price for non cooperative exporters has been determined on the basis of transactions of imports during the POI based on the information made available by DGCI&S. The CIF export price has been adjusted for expenses on account of overseas freight, overseas insurance, inland freight and handling charges to arrive at ex factory export price. The ex-factory price determined comes to US\$ \*\*\*/MT.

#### **E.8 Normal value for Chinese Taipei**

24. In view of non-cooperation by exporter, the normal value has been constructed on the basis of facts available as per Rule 6(8). The normal value has been constructed on the basis of raw material at international prices, consumption norm and conversion cost of the domestic industry. To this, profit @ 5% has been added to determine normal value. By this methodology the normal value has been constructed as US\$ \*\*\*/MT.

#### **E.9 Export price for non-cooperating exporters from Chinese Taipei**

25. Export price for non cooperative exporters has been determined on the basis of transactions of imports during the POI based on the information made available by DGCI&S. The CIF export price has been adjusted for expenses on account of overseas freight, overseas insurance, inland freight and handling charges to arrive at ex factory export price. The ex-factory price determined comes to US\$ \*\*\*/MT.

## E.10 Dumping Margin

26. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority has determined the dumping margin as under:

Exporter/Producer	Normal Value US\$/KG	Export Price US\$/KG	Dumping Margin US\$/KG	Dumping Margin %
China PR	***	***	***	41.73
Korea ROK	***	***	***	65.31
Chinese Taipei	***	***	***	50.70
Brazil	No dumping margin has been estimated as no import was reported during POI.			

27. It is noted that the dumping margins are significant.

## F Methodology for Injury Determination and Examination of Causal Link

### F.1 Examination by the Authority

28. The Authority has taken note that for the sunset review, the relevant provisions of Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act read as under:

*"The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:*

*Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension."*

29. Rule 23 of the Anti-dumping Rules provide for procedure for conducting sunset review. For conducting the review, the provisions of Rule 6,7,8,9, 10, 11, 16,17,18,19 and 20 have been made applicable. The Authority notes that as per Rules, present state of injury is to be assessed in the sunset review.

30. For the purpose of assessing present state of injury, Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential

negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

31. The Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

(A) **Volume Effect:** Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry:

32. The transaction-wise import data from DGCI&S has been relied upon for analyzing the imports from all sources. The data shows that the imports from subject countries has declined significantly from 30% in the base year to 2% in the POI. During the same period, the imports from countries attracting anti dumping duty has increased significantly from 35% to 96%. The imports from other countries has declined sharply from 35.22% to 1.84%. It has also been noted that the import prices from subject countries were higher as compared to countries attracting anti dumping duty in 2004-05, 2005-06 and 2006-07. The imports prices during POI from subject countries were slightly lower than the imports from countries attracting anti dumping duties.

	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Imports (in MT)				
China PR	2437	569	311	127
Korea RP	750	1283	645	167
Chinese Taipei	79	155	34	103
Brazil	0	0	17	0
Subject countries	3266	2007	1007	398
Countries attracting anti dumping duty	3856	7910	12869	16156
Other countries	3871	3425	122	206
Total imports	10993	13342	13998	16760
Share in imports	%			
Subject countries	29.71	15.04	7.19	2.37
Countries attracting anti dumping duty	35.08	59.29	91.93	96.40
Total imports	35.21	25.67	0.88	1.23

### **Assessment of demand, Import volume and market share**

33. The demand has been calculated as sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all the sources. It has been noted that demand of the product has increased by approximately 32% in POI as compared to base year. The share of the domestic industry shows the declining trend and its share has declined from 46% in the base year to 38% in the POI. The share of imports from subject countries has declined steeply from 16% to 1% during the same period. The imports

from other countries including countries attracting anti dumping duty the share has increased from 38% to 61%.

Demand in MT	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Sales of Domestic industry	9508	10433	10612	10284
Imports - Subject Countries	3266	2007	1007	398
Imports - Other Countries	7727	11335	12992	16362
Demand	20501	23775	24611	27044
Market Share %				
Domestic Industry	46%	44%	43%	38%
Imports - Subject Countries	16%	8%	4%	1%
Imports - Other Countries	38%	48%	53%	61%

#### Capacity, production & capacity utilization

34. Capacity, Production and Capacity Utilization of the domestic industry is given in the following table:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (POI)
Capacity (MT)	14000	14000	14000	14000
Trend	100	100	100	100
Production (MT)	10231	9712	11697	9894
Trend	100	95	114	97
Production-others-MT	3827	4013	2364	4357
Total production (MT)	14058	13725	14061	14251
Capacity Utilization%	100.41%	98.04%	100.44%	101.79%

35. Regarding capacity, it has been clarified by the domestic industry that the actual capacity for the PUC was determined on the basis of actual capacity available reduced by quantity determined for other grades of polyols, i.e. non-PUC. After taking into account the production of the other grade of polyol, it has been noted that the capacity utilization was more than 100% in 2004-05, 2006-07 and 2007-08. It has been argued that the capacity utilization would not indicate the clear position, the actual production has shown clear decline despite an increase in the demand. In this regard, the Authority has noted that when the capacity has been used both for production of PUC and non-PUC and available capacity for PUC depend upon the production of non-PUC, the production of PUC is bound to decline if available capacity is diverted for production of non-PUC. The position is clearly reflected in the capacity utilization of the domestic industry which remain fully utilized during the injury period.

36. It has been noted that the domestic industry has not changed its capacity from the base year to POI. The production of the goods has shown declining trend and declined by 337 MT in POI as compared to base year. The production as compared

to immediate preceding year declined by 1803 MT. The decline in production when capacity is fully utilized cannot be considered as sign of injury.

### **Sales**

37. Sales Volume of the domestic industry is given in the following table:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales of domestic Industry - MT	9508	10433	10612	10284
Trend	100	110	112	108
Sales Value (Rs Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	122	122	100

38. The sale of the domestic industry has increased by 8% in POI as compared to base year. In quantitative term, it increased by 776 MT as compared to base year. As compared to immediate preceding year, the sale has declined by 328 MT.

### **(B) Price effect of imports**

39. For calculating the undercutting of selling price of the domestic industry by the imports from subject countries, a comparison for subject goods during the period of investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, the rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. It has been noted that the price undercutting by imports from subject country continued throughout the injury period.

40. It has been noted that the price undercutting from the subject countries were negative from 2004-05 to 2007-08 except in case of Korea. The undercutting was in the range of approximately 3% during the POI. The imports from subject countries on weighted average basis did not show any undercutting during the injury period.

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Net Sales Realization Rs/MT	***	***	***	***
<b>Landed Price- Subject Countries</b>				
China PR	88595.19	97912.11	96303.5	80817.81
Price undercutting	***	***	***	***
Price undercutting %	***	***	***	***
Chinese Teipei	104923.4	95449.36	97696.05	76901.52
Price undercutting	***	***	***	***
Price undercutting %	***	***	***	***
Korea ROK	83968.77	93167.02	90567.54	70512.54
Price undercutting	***	***	***	***
Price undercutting %	***	***	***	***
Subject countries	87925	94689	92654	74462
Price undercutting	***	***	***	***
Price undercutting %	***	***	***	***

### Price Underselling

41. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. For the purpose of this analysis, weighted average Non-Injurious Price(NIP) of the domestic industry (worked out on the basis of the costing information of the domestic industry) have been compared with landed value of imports from the subject countries. The analysis shows that the landed values of subject goods from subject countries were much below the non-injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin was within a range of 25-35% for subject goods from subject country during the POI.

<b>Price Underselling (Rs./MT)</b>	
<b>Subject Countries</b>	
Brazil	*
China	***
Korea	***
Taiwan	***
<b>Total</b>	***
<b>Price Underselling (%)</b>	
<b>Subject Countries</b>	
Brazil	*
China	***
Korea	***
Taiwan	***
<b>Total</b>	***
<b>Price Undercutting (%) - Ranges</b>	***



Subject Countries	
Brazil	*
China	***
Korea	***
Taiwan	***
Total	***

\* There was no imports from Brazil during POI.

## F.2 Examination of other Injury Parameters

42. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed hereunder:-

43. The profitability, profits and cash flow of the domestic industry are given in the following table:-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales Value (Rs Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	122	122	100
Selling Price/Unit	***	***	***	***
Trend	100	111	109	93
Cost (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Cost /Unit	***	***	***	***
Trend	100	111	114	114
Profit (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	127	53	-237
Profit/MT	***	***	***	***
Trend	100	116	48	-219
Profit/ Loss (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Add: Depreciation (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Cash Flow (In Rs. Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	119	62	-172
Cash Flow/Unit	***	***	***	***
Trend	100	108	56	-159

44. The data of the domestic industry shows that the cost of sale per unit has increased to 114 (indexed) in POI as compared to 100 of base year. In terms of

2728 4/11-8

value, the cost of sale increased by Rs.\*\*\* PMT. During the same period the net sales realization of the domestic industry declined to 93 (indexed) in POI as compared to 100 of the base year. In terms of value the sale price declined by Rs.\*\*\* PMT. The profit per MT from 100 (indexed) in the base year turned to loss of Rs.\*\*\* in the POI.

### Cash Flow

45. The domestic industry is multi products company. Therefore, cash profit situation of the domestic industry has been determined. Cash profit declined from base year to POI and in indexed form decreased from 100 in base year to become -159 in POI.

### Return on capital employed

46. The Information regarding return on capital employed is given in the table below:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Net Fixed Assets Rs. Lacs	***	***	***	***
Working Capital Rs. Lacs	***	***	***	***
Capital Employed	***	***	***	***
Profit before Interest	***	***	***	***
ROCE	***	***	***	***
Indexed	100	112	58	-249

47. The data shows that the capital employed has declined by 20% in POI as compared to base year. The return on capital employed ( NFA basis) was positive in base year, turned negative in POI.

### Employment and Wages

48. Employment & Wages levels of the domestic industry is given in the following table:

	April 04 to March 05	April 05 to March 06	April 06 to March 07	POI
No of Employees	***	***	***	***
Trend	100	90	100	100
Wages Total (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	93	120	113

49. The data shows that number of employees remained same in POI as compared to base year. The wages to employees increased by 13% during the same period.

**Productivity**

50. Productivity of the domestic industry, as reflected in terms of production per employee, is given in the following table

	April 04 to March 05	April 05 to March 06	April 06 to March 07	POI-
	***	***	***	***
Production (MT)	***	***	***	***
Employees	***	***	***	***
Production per Employee (MT)	***	***	***	***
Trend	100	105	114	97

51. The productivity of the domestic industry i.e. production per employee declined during the POI as compared to base year on account of reduction in the production.

**Growth**

52. The demand, sale and cost of sales show positive growth. The production, selling price, profitability, PBIT and return on capital employed shows negative growth.

**Inventory**

53. The inventories of the domestic industry have increased from base year to POI. It was equal to 24 days of sale in base year and increased to 31 days of sales in POI.

	April 04 to March 05	April 05 to March 06	April 06 to March 07	POI
	***	***	***	***
Opening Stock (MT)	***	***	***	***
Closing Stock (MT)	***	***	***	***
Average Stock (MT)	***	***	***	***
Trend	100	92	104	139
As a % of Sales Volume	***	***	***	***
Indexed	100	84	93	128
No. of days of stock. held	***	***	***	***
Indexed	100	84	93	128

**Factors affecting domestic prices: -**

54. In order to ascertain the factors affecting the domestic prices, the Authority considered various available information. It has been noted that cost of production has increased by 14% in POI as compared to base year. It has also been noted that the imports were not undercutting the prices of the domestic industry in the market. Basic customs duties declined from 20% in 2004-05 to 10% in POI, the landed value however continue to increase till 2006-07 however, it declined significantly in POI.

**The magnitude of the margin of dumping: -**

55. Authority notes that dumping margin from subject countries were significant during POI.

**Ability to raise capital investments: -**

56. No investment plan has been intimated by the domestic industry.

**F.3 Overall assessment of Current Injury**

57. The demand of goods show growth of 32% in POI as compared to base year. The production has declined during the same period. The sales, however, registered growth of 8%. It has been noted that production facility is common for PUC and non-PUC goods. The production of PUC goods depend on available capacity after production of non-PUC goods. As capacity remains fully utilized, therefore, decline in production cannot be treated as sign of injury. It has been noted that there is significant gap in demand and supply in the market. Therefore, decline in market share of domestic industry cannot be considered as sign of injury.

58. The cost of sales increased by 14% in POI as compared to base year. The selling price however declined to 93 (indexed) in POI as compared to base year. The profit per unit in base year turn to loss in POI. Consequently profit (PBIT) turned to loss in POI as compared to profit in base year. The Return on Capital Employed also turned negative in POI from profits in base year. The financial performance indicates injury to the domestic industry.

**F.4 OTHERS KNOWN FACTORS**

59. The authority has also examined following known factors other than dumped imports which may have been causing or contributing injury to the domestic industry:

**Volume and prices of imports from other sources**

60. It has been seen that significant imports have been reported from other countries attracting anti dumping duties (USA, Singapore and Japan). The imports from these countries constitute 35.08%, 59.29%, 91.93% and 96.40% in 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 respectively. It has further been noted that import prices from these countries in year 2004-05, 2005-06 and 2006-07 were lower than

the import prices from subject countries under review. In 2007-08, the prices from subject countries were slightly lower than the prices from the other countries.

61. The imports from other sources (other than countries attracting anti dumping duty including the subject countries under this review) were 35.22%, 25.67%, 0.88% and 1.84% in year 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 respectively. The prices from these countries were higher than other countries except in year 2004-05 when the prices were lower than the subject countries under review. However, the trend of imports indicate that imports from countries attracting anti dumping duties (except countries under review) captured the imports market as its share constituted 91.97% in 2006-07 and 96.40% in POI. This is despite the fact that import prices from these countries were slightly higher, in POI than the import prices from subject countries under review.

#### **Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

62. Demand of the product under consideration has not registered positive growth. However, it has been noted that the domestic industry was encountering difficulties in sales of Polyol on account of restricted supply of TDI, a complementing raw material for manufacture of PU foam. Also, the domestic industry does not have extra capacity to meet the demand in the market. Contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry.

#### **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

63. The subject goods are freely importable and there is no evidence of trade restrictive practices prevailing in the domestic market. This factor could not have been the reason to cause injury to the domestic industry. The subject goods from other countries appeared to have dominated the imports in the market.

#### **Development of technology and export performance**

64. Technology for production of the product has not undergone any significant change. Development in technology is not a factor of injury.

#### **Productivity of the Domestic Industry**

65. Productivity of the domestic industry measured as production per employee has shown that productivity has declined on account of decline in production.

#### **F.5 Causal link & Likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury**

#### **F.6 Examination by Authority**

66. The Authority notes that during the continuation of duty, the domestic industry continue to utilize capacity. The available capacity for product was available after production of non-PUC goods. The decline in production of PUC can be attributed to the diversion of capacity to non-PUC goods. In the POI, however, it declined to 88%.

The Authority has also noted that the domestic industry was encountering difficulty in sales of Polyol on account of restricted supply of TDI, a complementary raw material for manufacture of PU foam. It has further been noted that another product Methylene Di Isocyanate (MDI), a complementary product for polyol, in the manufacture of polyurethanes, which were also being imported in the country by the applicant or by other also posed difficulties as the prices of this product doubled and its shortage in the market posed a serious threat to this line of business. It has been stated in the 20<sup>th</sup> Annual Report that the tight supply situation and higher price scenario of both MDI and TDI continued to pose problem in the marketing of the polyol formulation. In 21<sup>st</sup> Annual Report, the difficulty about the restricted availability and higher price of imported TDI due to shutdown of plants, has been stated. It has also been stated that the company could maintain the sale of polyol as the business supplier of TDI maintain their supplies regularly.

67. It has further been noted that imports from countries attracting anti dumping duties (except the countries under review) were consistently increasing its share in the imports. The imports from these countries constitute 35.08%, 59.29%, 91.93% and 96.40% in 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 respectively. It has also been noted that prices from these countries were lower than the imports from subject countries under review except in POI. In the POI, imports prices from subject countries were slightly lower than the other countries attracting anti dumping duties.

68. The Authority has also noted that when reference price for these subject countries become irrelevant and imports were at higher prices, the domestic industry did not show any interest in getting the reference price for these countries reviewed. The domestic industry continued to sell goods at lower prices indicating that the domestic industry was not affected by such variation in the prices. It has been submitted by domestic industry that cost of subject goods for the producers world over as well as for the domestic industry has increased significantly over the past recent years due to rise in raw material prices. The duties level determined in FSP-1 original investigation remain effective till 4<sup>th</sup> February 2008 and in the FSP-2 original investigation become lower than the cost of subject goods of the domestic industry in the POI. Therefore, the subject goods from the subject countries as well as from the countries in FSP-1 continued coming at the prices higher than the reference prices. It is for this reason that they filed MTR application. The same was not accepted by the Authority and domestic industry was therefore continued to suffer by keeping it prices at un-remunerative level due to dumped prices offered by the subject countries as well as by the countries in FSP-1. The Authority has examined the submissions and noted that the reference price for the subject countries had become ineffective as imports were coming at price higher than that offered by the domestic industry. The reference price for the subject countries were lower than the reference prices fixed in the FSP-1. The domestic industry while preferring sunset review of FSP-1 should have also preferred MTR for the subject countries whereas the domestic industry filed the MTR on 3<sup>rd</sup> March 2008 when it was due for the sunset review. The domestic industry was advised to file the SSR, however, the domestic industry preferred to wait for the suo moto initiation of SSR by the Designated Authority and preferred to file information well after the time permitted indicating lake of urgency on the part of domestic industry.

69. It has also been noted that no imports from Brazil has been reported in the POI and very small quantity of imports has been reported in 2006-07. The anti dumping duty in form of reference price had become irrelevant even then the imports from Brazil did not take place indicating the negative trend of imports from Brazil.

70. During the injury period, the share of imports from other countries attracting anti dumping duty has increased and captured the market share of the subject countries. The anti dumping duties on other countries attracting anti dumping duty have been reviewed and revised with effect from 6<sup>th</sup> February, 2008. The impact of revised anti dumping duty has not been captured in the injury analysis of this review. Though there is no undercutting, the import prices of other countries attracting anti dumping duty, subject countries and selling price of the domestic industry shows some relationship as prices of import and selling price of the domestic industry have declined in the POI. It has been noted earlier that dumped imports continued to take place from China PR, Chinese Taipei and Korea RP as has been assessed in the earlier section of this findings. In case of revocation of anti dumping duty from subject countries (excluding Brazil), the imports from other countries attracting anti dumping duty are likely to shift to subject countries (excluding Brazil). Therefore, there is a likelihood of continuous injury to the domestic industry from imports from subject countries (excluding Brazil).

#### **G. FINAL FINDINGS**

71. The Authority after considering the foregoing concludes that:

- a. Subject goods originating in or exported from China PR, Chinese Taipei and Korea RP have been exported to India below their normal value, resulting in dumping;
- b. Subject goods from Brazil have not been exported to India during the POI, therefore, the current dumping from Brazil cannot be determined. The trend of imports indicates that imports from Brazil may not resume.
- c. in case of revocation of anti-dumping duties on the subject goods from China PR, Chinese Taipei and Korea RP, the dumping is likely to continue, and the dumped imports from these countries likely to continue injury to the domestic industry.

#### **Indian industry's interest & other issues**

72. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

## K. Recommendations

73. In view of positive determination of likelihood of dumping and injury on account of imports from China PR, Chinese Taipei and Korea RP the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from these countries. However, considering the current level of dumping from China PR, Chinese Taipei and Korea RP and performance of the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, Authority considers it necessary and recommends anti-dumping duty on imports of subject goods from Chinese Taipei and Korea RP in the form and manner described hereunder.

74. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, Definitive antidumping duty as the difference between the reference price and the landed value as indicated in Col 9 of the table below, if the landed value at the time of importation is below the value indicated at Col.9 of the table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the China PR, Chinese Taipei and Korea RP. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Grade	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3907 20	Flexible slabstock polyol	Molecular weight 3000-4000	China PR	China PR	Any	Any	2601	MT	USD
2	Do	Do		China PR	Any country other than China PR	Any	Any	2601	MT	USD
3	Do	Do		Any country other than country/ies attracting anti dumping duty	China PR	Any	Any	2601	MT	USD
4	Do	Do		Korea RP	Korea RP	Any	Any	2601	MT	USD
5	Do	Do		Korea RP	Any country other than Korea RP	Any	Any	2601	MT	USD
6	Do	Do		Any country other than country/ies attracting anti dumping duty	Korea RP	Any	Any	2601	MT	USD



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Do	Do		Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	2601	MT	USD
8	Do	Do		Chinese Taipei	Any country other than Chinese Taipei	Any	Any	2601	MT	USD
9	Do	Do		Any country other than country/ies attracting anti dumping duty	Chinese Taipei	Any	Any	2601	MT	USD

75. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority